वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

1994 - 95

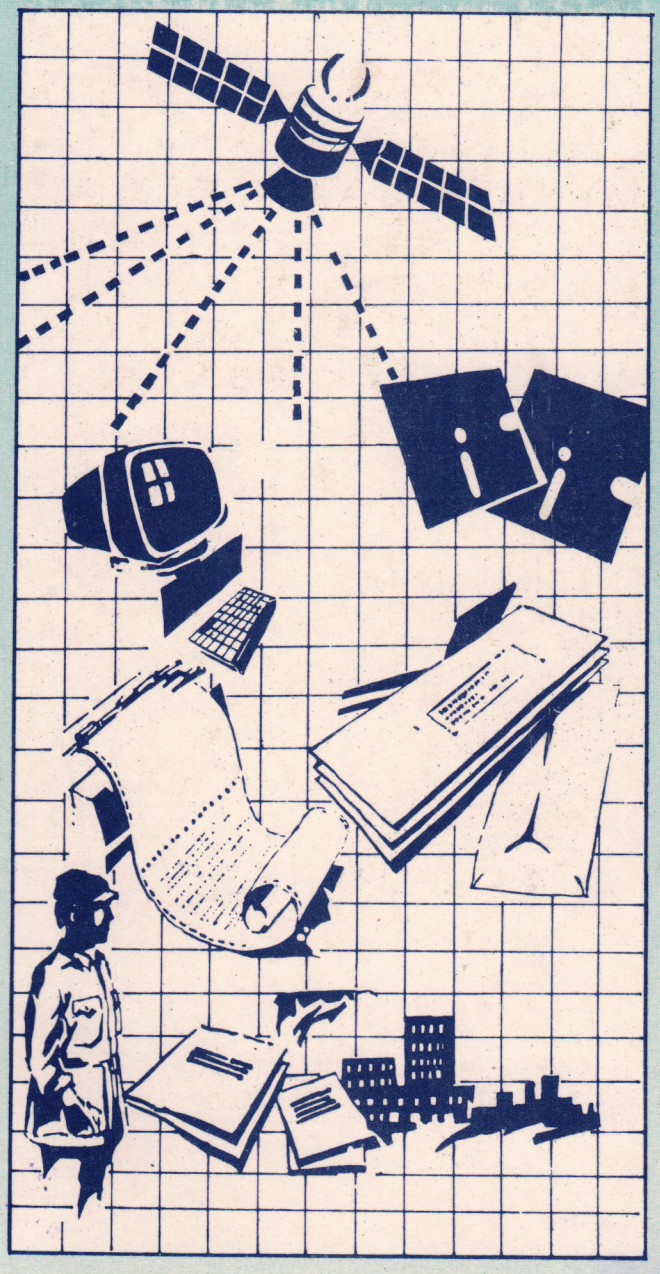

सत्यमेव जयते

भारतीय डाक विभाग

Department of Post, India

Post Shoppe in Parliament Street Head Post Office, New Delhi.

विषय सूची

भाग 1 : वार्षिक रिपोर्ट (1993-94)

पुनरीक्षा	5
संगठन	7
डाक प्रचालन	8
डाक वित्त	16
मानव संसाधन	20
भाग 2 : वार्षिक रिपोर्ट (1994-95)	23

CONTENTS

Part 1 : Annual Report (1993-94)

Overview	28
Organisation	30
Postal Operations	31
Postal Finance	39
Human Resources	43
Part 2 : Annual Report (1994-95)	46
Statistical Supplements	50

भाग-1
वार्षिक रिपोर्ट
1993-94

पुनरीक्षा

भारतीय डाक प्रणाली के चार स्तंभ है- इसकी सार्वभौमिकता, सेवाओं के अलग-अलग घटकों का सांविधिक संरक्षण, दरों का संसदीय विनियमन तथा डाक या धन प्रेषण के लिए समुचित दायित्व। डाकघर नेटवर्क में डाकघरों की संख्या 1,52,786 हो गई है, इनमें से 89 प्रतिशत डाकघर गांवों में स्थित हैं, जिनमें से अधिकांश डाकघर स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत खोले गए हैं। यह हमारे उस लक्ष्य को सुस्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं, जिस लक्ष्य को भारतीय डाक प्रणाली ने अत्यंत श्रमसाध्य रूप से वहन किया है। संसाधनों तथा उद्यमों पर अत्यधिक दबाव होने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्र के प्रति 23.12 वर्ग कि०मी० तथा शहरी क्षेत्र के प्रति 3.16 वर्ग कि०मी० क्षेत्र के लिए एक डाकघर या ग्रामों में प्रति 4612 व्यक्तियों तथा एक कस्बे में या शहर में प्रति 12,924 व्यक्तियों के लिए एक डाकघर का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। डाक की अपर्याप्तता तथा उसके क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना, देश में प्रत्येक प्रेषण स्थल पर प्रत्येक स्थान पर जहां भी किसी व्यक्ति की डाक है, वह प्रतिदिन डाकिए द्वारा वितरित की जाती है। भारतीय डाक प्रणाली इस दृष्टि से न केवल अद्वितीय है बल्कि इसे कार्यकुशल बनाए रखना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। भारत में डाक सेवाएं अन्य सभी देशों की तुलना में सबसे कम दामों पर सुलभ हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है कि प्रेषक तथा प्रेषिती, दोनों ही के लिए, डाक के महत्व से इसके सर्वोच्च सरोकार समान रूप से जुड़े हुए हैं। वर्ष 1993-94 में देशी मूल की 3549 मिलियन अपंजीकृत डाक वस्तुएं तथा 334 मिलियन पंजीकृत डाक वस्तुएं देश में वितरित की गई, जो गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 294 मिलियन तथा 20 मिलियन अधिक हैं और जो 8.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि को दर्शाती है। डाक ने 31,826 मिलियन रुपये के कुल मूल्य के 98.7 मिलियन मनीआर्डर भी वहन किए। मनीआर्डरों की संख्या हालांकि 6.6 मिलियन या 6.3 प्रतिशत कम हो गई है, किंतु इसके मूल्य में 2,702 मिलियन रुपये या 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय डाक, संख्या तथा मूल विषयक विविधता, दोनों ही प्रकार से अभी भी एक अन्य आयाम है। ये संख्याएं प्रति व्यक्ति, अमरीका या जापान जैसे देशों के साथ तुलनीय मात्रा के दर्जे को संकेतित नहीं करतीं। किंतु, डाक पर की जाने वाली कार्रवाई और डाक वितरण के कार्य की दृष्टि से इसका महत्व इन देशों की तुलना में कम न होकर, स्वतः प्रमाणित है। एक अत्यंत विशाल और संश्लिष्ट नेटवर्क में डाक पर कार्रवाई करना और डाक का पारेषण, भले ही वह इस संगठन की या इसके वास्तविक कार्य की बात हो, कोई मामूली बात नहीं है, उन डाक पतों की संभावित कुल संख्या की तो बात ही छोड़िए जो अतिसंकुल और दूरदराज के इलाकों में स्थित है।

शहरी क्षेत्रों की चुनौतियां और स्वचलन

छः शहर अर्थात् बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बेंगलूर और हैदराबाद, जिनकी कुल जनसंख्या 35.57 मिलियन है, प्रतिदिन अपने शहरों से भेजे जाने वाली घरेलू डाक की 7 मिलियन वस्तुओं का लेखा-जोखा रखते हैं, जो पूरे देश के कुल डाक परिवात का करीबन 59 प्रतिशत है। इन महानगरों की डाक और शेष भारत की डाक-मात्रा में अत्यधिक असमानता है जिससे महानगरों की डाक प्रणाली को डाक के निपटान के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। निपटान केंद्रों पर डाक की इन विशाल मात्राओं से उत्पन्न समय-दबावों का इस समय डाक संचालन में बिना किसी विलंब के ध्यान रखना एक गंभीर तथ्य है तथा आने वाले समय में व्यापक आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के कारण महानगरीय डाक में बेतहाशा वृद्धि होने से इसकी गंभीरता और अधिक बढ़ जाएगी। हाथ द्वारा निपटाए गए कार्यों की एक सीमा निश्चित होती है, चाहे वे कितनी ही निष्ठा से क्यों न किए गए हों? विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व इस बात को महसूस किया और एक उत्कृष्ट योजना और उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल, 1993 को बंबई में देश का पहला स्वचालित डाक छंटाई केंद्र खोला गया जिसकी क्षमता 24 घंटे में 1.2 मिलियन पत्रों की छंटाई की है। शहर की डाक प्रचालन संबंधी कई समस्याओं के समाधान में यह केंद्र धीरे-धीरे अपनी भूमिका का महत्व सिद्ध कर रहा है। इस प्रकार का दूसरा केंद्र सितंबर, 1995 में मद्रास में चालू किया जाएगा। इन दोनों केंद्रों की लागत 39.7 मिलियन रुपये है। इन केंद्रों ने भविष्य के लिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि परंपरागत व्यवस्थाएं प्रत्येक स्थान पर कार्यकुशल नहीं हो सकतीं।

स्वचलन, प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक एक संस्कृति है। ग्राहकों के साथ अपने बाह्य स्वरूप में आन्तरिक कार्य से परे डाक पर कार्रवाई करने को डाक ने अनुकूलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। वर्ष 1991 के आरंभ में सात शहरों अर्थात् बंबई, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, बेंगलूर, हैदराबाद और लखनऊ के 22 डाकघर, एक ही काउंटर से स्पीड और अन्य विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के द्वारा काउंटर कार्यों के स्वचलन में अग्रणी बने। यह एक तात्कालिक सफलता थी और इस सफलता ने बड़ी मात्रा में और अधिक काउंटर सेवाओं का स्वचलन करने का महत्वपूर्ण निर्णय

लेने की दिशा में कार्य किया। 657 डाकघरों में अब तक स्वचालित काउंटर सेवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं अथवा मार्च, 1995 तक उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसे प्रत्येक काउंटर में पंजीकृत, बीमाकृत और मूल्यदेय पत्र स्वीकार किए जाते हैं और इन काउंटरों पर एक लेनदेन को एक मिनट के भीतर निपटा लिया जाता है। इससे शहरी डाकघरों की लंबी कतारें, जो डाकघरों पर अत्यंत भारी दबाव उत्पन्न करती थीं, अब बीते समय की बात बनकर रह गई हैं और भारत, डाकघर की पंक्ति में खड़े अंतिम ग्राहक को मात्र 5 मिनट में निपटाने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम यह है कि अब तक देश के 15 डाकघरों में डाक-टिकटों की बिक्री को छोड़कर पूर्णतः स्वचालित काउंटर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और मार्च, 1995 तक इन डाकघरों की संख्या 53 हो जाएगी।

काउंटर सेवाओं के लिए इन स्वचलन उपायों पर विभाग ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 में कुल मिलाकर 85 मिलियन रुपये खर्च किए। इसके अतिरिक्त, डाक जीवन बीमा और डाकघर बचत बैंक कार्यों का भी स्वचलन किया गया है जिससे डाक प्रणाली में संपूर्ण परिवर्तन आ गया है।

वर्ष 1994-95 के लिए स्वचलन पर 390.30 मिलियन रुपये का कुल व्यय अनुमानित किया गया है और वर्ष 1995-96 में यह राशि 481.60 मिलियन रुपये होगी। अगले वर्ष 500 और डाकघरों में पूर्णतः स्वचालित सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। निष्कर्ष यह है कि इससे ग्राहकों को प्राप्त होने वाली सेवा में जो वृद्धि होगी, वह आंकड़ों और आकलन से कहीं अधिक होगी।

वित्त-व्यवस्था और मूल्य-निर्धारण-व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता

डाक का वित्त-साधन निरंतर घाटे में जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 1993-94 में 312.7 मिलियन रुपये की राजस्व वृद्धि के बावजूद घाटा पिछले वर्ष के 918.10 मिलियन रुपये से बढ़कर 2,070.9 मिलियन रुपये हो गया। इसके परिणामस्वरूप डाक विभाग और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामले उठे। लागत में वृद्धि की अपेक्षा दरें काफी कम हैं और लागत में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे हरेक वर्ष घाटा होता रहा है।

प्रतीयमानतः घाटा खाते के दोनों पक्षों को संतुलित करने का विषय नहीं है। उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रयोक्ताओं से स्पष्ट मांग होती रही है जो अंशतः मानव कार्य-निष्पादन और काफी हद तक अंतः-संरचनात्मक साधन हेतु निवेश से संभव है। ये साधन हैं - बेहतर परिसर, अनुकूल कार्य सुविधाएं, दक्ष उपस्कर, परिवहन सुविधा आदि। घाटा निवेश को नियंत्रित कर लेता है जिससे सेवा की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

1993-94 के राजस्व आंकड़ों से विरोधाभासी संकेत मिलते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में केवल 2.91 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि हुई है जबकि डाक के परिमाण में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त क्षेत्रों में डाक के परिमाण में काफी वृद्धि हुई है, जैसे-लेटर कार्ड में 32.52 प्रतिशत, पोस्टकार्ड में 89.57 प्रतिशत और समाचार-पत्र में 92.03 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। टेलीविजन प्रतियोगिताओं जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पोस्टकार्ड के प्रयोग में भारी वृद्धि ऐसा ही एक कारण है। इस प्रकार डाक का सामाजिक प्रयोजन धीरे-धीरे नष्ट होता जाता है। यह सूक्ष्म विश्लेषण और सामाजिक रूप से विवेकपूर्ण दर नीति का एक पक्ष है।

सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अंतः संरचना के रूप में अपनी वर्तमान और भावी भूमिका निभाने हेतु डाक विभाग की सभी क्षेत्रों से व्यापक समर्थन की आवश्यकता है। डाक विभाग अपनी विकासशील व्यापार स्थिति से सामंजस्य रखते हुए एक उचित कानूनी स्थिति, वित्तीय और प्रबंधात्मक नम्यता की अपेक्षा करता है।

भारतीय डाक और इसका भविष्य

जैसाकि 1989 में वाशिंगटन कांग्रेस की सामान्य परिचर्चा में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा सम्पारित किया गया है तथा 1994 के सिओल कांग्रेस द्वारा दुहराया गया है कि डाक का आदर्श है- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी करना। प्रत्येक देश में डाक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। भारत में ऐसे अनेक कदम उठाये गये हैं और इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है जो डाक की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। लक्ष्य यह है कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें नवीनतम संचार सुविधा हो। यह लक्ष्य नए विधि-निर्माण, वाणिज्यिक प्रोत्साहन, वित्तीय पुनर्अनुकूलन संरचनात्मक परिवर्तन और कर्मचारियों के एकनिष्ठ सहयोग से प्राप्त होगा जिसके उपरांत भारतीय डाक प्रणाली विश्व की सर्वोत्तम डाक प्रणाली का मुकाबला कर पाएगी। डाक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही है ताकि 21 वीं शताब्दी में यह देश में किसी से भी कम नहीं हो।

संगठन

संचार मंत्रालय के एक विभाग के रूप में डाक विभाग का सृजन जनवरी, 1985 में किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग, संचार राज्यमंत्री श्री सुखराम (स्वतंत्र कार्यभार) के तहत ही कार्य करता रहा।

मुख्यालय

विभाग का प्रबंध डाक सेवा बोर्ड देखता है। बोर्ड के अध्यक्ष, डाक विभाग के सचिव तथा डाक महानिदेशक भी हैं। बोर्ड में तीन सदस्य हैं, जिनके पास प्रचालन, विकास तथा कार्मिक संविभाग हैं। इसके अलावा बोर्ड में एक वित्त सलाहकार भी हैं।

बोर्ड की सहायता के लिए एक सचिव है जो वरिष्ठ उप महानिदेशक (गुणवत्ता प्रबंध) भी हैं। 18 उप महानिदेशकों की सहायता से बोर्ड देश में डाक सेवाओं के प्रबंध का निर्देशन व पर्यवेक्षण करता है।

सर्किल

विभाग के प्रचालन दायित्वों को 19 डाक सर्किल वहन करते हैं। एक सर्किल में एक या एकाधिक राज्य/संघशासित क्षेत्र होते है और सर्किल का अध्यक्ष मुख्य पोस्टमास्टर जनरल होता है तथा सर्किल को सामान्यत: क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिनमें फील्ड यूनिटों का समूह होता है, जिन्हें डिवीजन कहा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में एक पोस्टमास्टर जनरल होता है जो मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को फील्ड में उच्च स्तरीय प्रबंध सहायता प्रदान करता है।

सर्किलों के अलावा, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में क्षेत्रीय डाक योजना इकाइयां हैं जो पोस्टमास्टर जनरल के पद के नियंत्रकों के अधीन हैं। नियंत्रक, डाक प्रचालनों की योजना तथा नियंत्रण में अनन्य रूप से व्यावसायिकता लाते हैं। एक सर्किल में मेल डिवीजन, स्टोर डिपो, स्टैम्प डिपो तथा मेल मोटर सेवा जैसी अन्य प्रकार्यात्मक डिवीजनें भी होती हैं।

भारतीय डाकघरों को प्रधान, उप तथा शाखा डाकघरों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। शाखा डाकघर आमतौर पर अतिरिक्त विभागीय डाकघर होते है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं। अधिकांश उप डाकघर विभागीय हैं और ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रधान डाकघरों को उनके कार्यभार तथा कर्मचारी की संख्या के अनुसार 5 श्रेणियों में श्रेणीकृत किया गया है, इनमें से सबसे बड़ा डाकघर बम्बई जी पी ओ और कलकत्ता जी पी ओ है तथा इनके उपरांत मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलूर, कानपुर, लखनऊ और देश के अन्य बड़े शहरों के जी पी ओ हैं।

सैना डाक सेवा का अध्यक्ष मेजर जनरल होता है। उसे अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा के बतौर नामोदिदष्ट किया गया है और साथ ही उसे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, सेना डाक सेवा सर्किल भी कहा जाता है। अधिकारी संवर्ग में तथा अन्य पदों में, जिनमें मेजर जनरल भी शामिल हैं, अधिकांश कार्मिकसिविल डाक सेवा से लिए जाते हैं।

स्थिति

दिनांक 1.4.94 की स्थिति के अनुसार डाक सेवा बोर्ड में श्री टी०ई० रमन, सचिव (डाक), महानिदेशक, डाक तथा अध्यक्ष डाक सेवा बोर्ड, श्री बी० परब्रह्म, सदस्य (कार्मिक), श्री एस०सी० महालिक, सदस्य (प्रचालन), श्री जी०एस० राजामणि, संयुक्त सचिव के बतौर सम्मिलित हैं तथा वित्तीय सलाहकार, डाक विभाग, बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। इस समय श्री एस०सी० महालिक डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष, श्री पी०के० बागची, सदस्य (विकास) श्री ए०वी०राव, सदस्य (कार्मिक), श्री सी० जे० मैथ्यू, सदस्य (प्रचालन) तथा श्री के०धीश, वरिष्ठ उप महानिदेशक तथा सचिव, डाक सेवा बोर्ड हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विश्व डाक संघ कार्यकारी परिषद तथा डाक अध्ययन सलाहकार परिषद के वार्षिक अधिवेशन अप्रैल और अक्तूबर, 1993 में क्रमश: बर्न, स्विटजरलैंड में आयोजित किए गए। इन अधिवेशनों में सचिव, डाक के नेतृत्व में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत आवधिक देयताओं पर वर्किंग पार्टी के तथा विश्व डाक संघ के पुनर्निर्माण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। "डाक विकास" पर सी सी पी एस की एक महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता करने के अलावा भारत ने "विकासशील देशों में ग्रामीण डाक सेवाओं में सुधार" तथा "नवीन उत्पाद विकास" से संबंधित दो महत्वपूर्ण विश्व डाक संघ अध्ययनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन महत्वपूर्ण अध्ययनों के लिए भारत रिपोर्टिंग देश था। एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने एशियाई प्रशांत डाक प्रशिक्षण केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की सितम्बर, 1993 में कोबे, जापान में आयोजित बैठक में भाग लिया। भारत ने वर्ष के दौरान सार्क देशों की पहली बैठक की मेजबानी की। भारतीय डाक प्रशासन ने "डाक सेवाओं का मशीनीकरण" पर पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद में सार्क डाक प्रशासनों के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नेपाल, भूटान श्रीलंका, पाकिस्तान तथा भारत के सहभागियों ने भाग लिया।

डाक पर भारत-चीन कार्य-समूह की एक बैठक भारत में नवम्बर, 1993 को आयोजित की गई।

डाक प्रचालन

प्रस्तावना

डाक प्रचालन को अनन्य रूप से पत्र-वितरण के लिए सामान्यतः एक अलग कार्य माना जाता है जो वस्तुतः पत्र-संग्रहण, छंटाई पारेषण, गंतव्य स्थान पर अंतिम छंटाई व वितरण जैसे बहुविध अंतः संबंधी प्रकार्यों की एक श्रंखला है। इसके अलावा पंजीकरण, मनीआर्डर, स्पीड पोस्ट आदेशों जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए आनुषंगिक गतिविधियां हैं। अधिकतम ग्राहक-संतुष्टि प्रदान करने के लिए प्रचालनों की इस बहुलता की सफलता एयरलाइन्स, रेलवे, रोडवेज तथा शिपिंग जैसी अन्य एजेंसियों की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। डाक संप्रेषण प्रणाली के अतिरिक्त डाक विभाग अन्य मंत्रालयों व विभागों की ओर से भी कुछ कार्य निष्पादित करता है। बचत बैंक तथा डाक जीवन बीमा जैसी सेवायें एजेंसी सेवाओं के रूप में जानी जाती हैं।

डाक नेटवर्क का विस्तार

डाकघरों की संख्या के संबंध में भारत का स्थान, विश्व की डाक प्रणालियों में सर्वप्रथम है। इसका श्रेय देश की विशालता और इसकी विशाल जनसंख्या को तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत डाक नेटवर्क को सामाजिक एकीकरण के, आर्थिक विकास तथा ग्रामीण पुनरुद्धार के एक साधन के रूप में विकसित करने के सरकार के कर्तव्यनिष्ठ प्रयास को भी जाता है। डाक संप्रेषण के विस्तार के मूल उद्देश्य को पूरा करने के अलावा, डाक सेवाओं के विस्तार ने साक्षरता प्रसार, रोजगार उत्पादन, लघु बचतों का संवर्धन तथा पिछड़े और दूर-दराज के इलाकों में उद्योगों की स्थापना जैसे सरकार के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी उल्लेखनीय योगदान किया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राष्ट्रीय डाक नेटवर्क में1,47,236 डाकघर

डाक घरों की संख्या

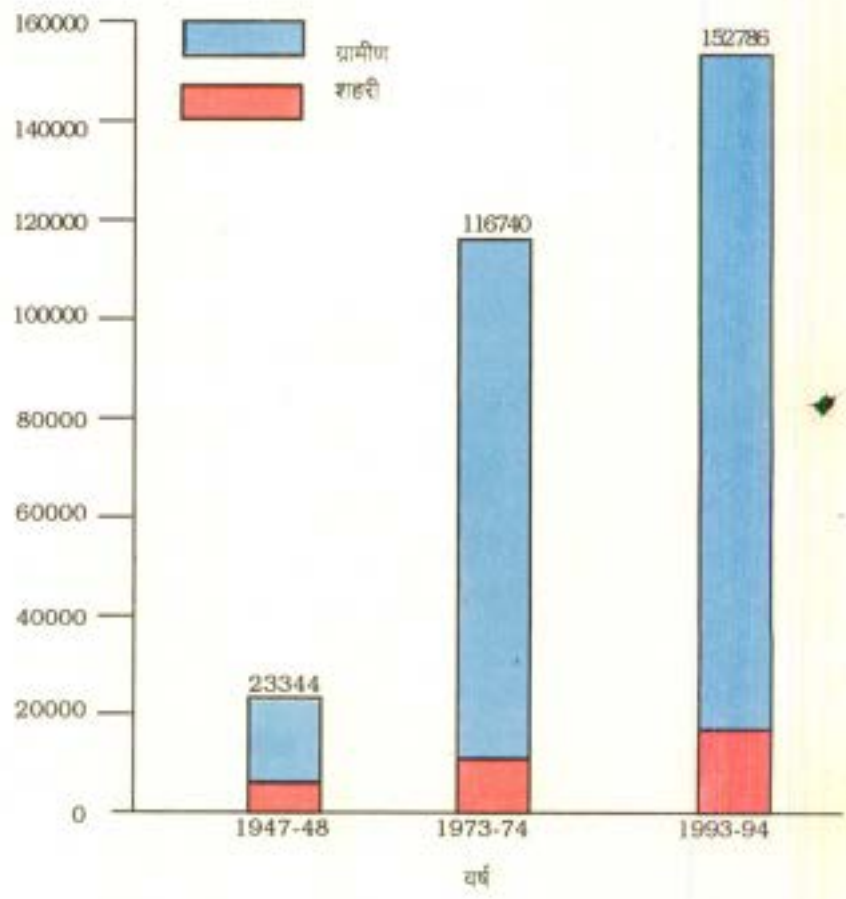

शामिल थे, इनमें से 16,249 डाकघर शहरी क्षेत्रों में तथा 1,30,987 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे। दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार देश में 1,52,786 डाकघर थे, इनमें से 16,804 डाकघर शहरी क्षेत्र में तथा 1,35,982 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार एक डाकघर औसतन 21.49 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को तथा 5527 व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है।

योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान 500 विभागीय उपडाकघर तथा 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लक्ष्य को मूल रूप से मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, संसदीय समिति द्वारा लगातार की जा रही इस मांग के संदर्भ में कि डाक सुविधाओं के विस्तार की गति बढ़ाई जाए, योजना कार्यनिष्पादन की समीक्षा करते हुए विभाग ने यह नोट किया कि उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत और अधिक डाकघर खोलने की संभावना है। तदनुसार, योजना आयोग से परामर्श करके अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य पहले ही आवंटित किए जा चुके संसाधनों के अंतर्गत,

1984-85 से डाक परियात
(राजस्व में समायोजित)

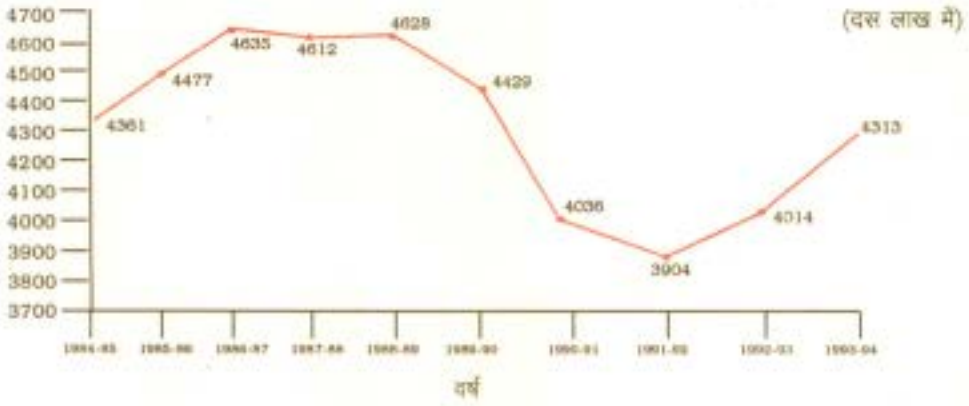

मदवार डाक परियात

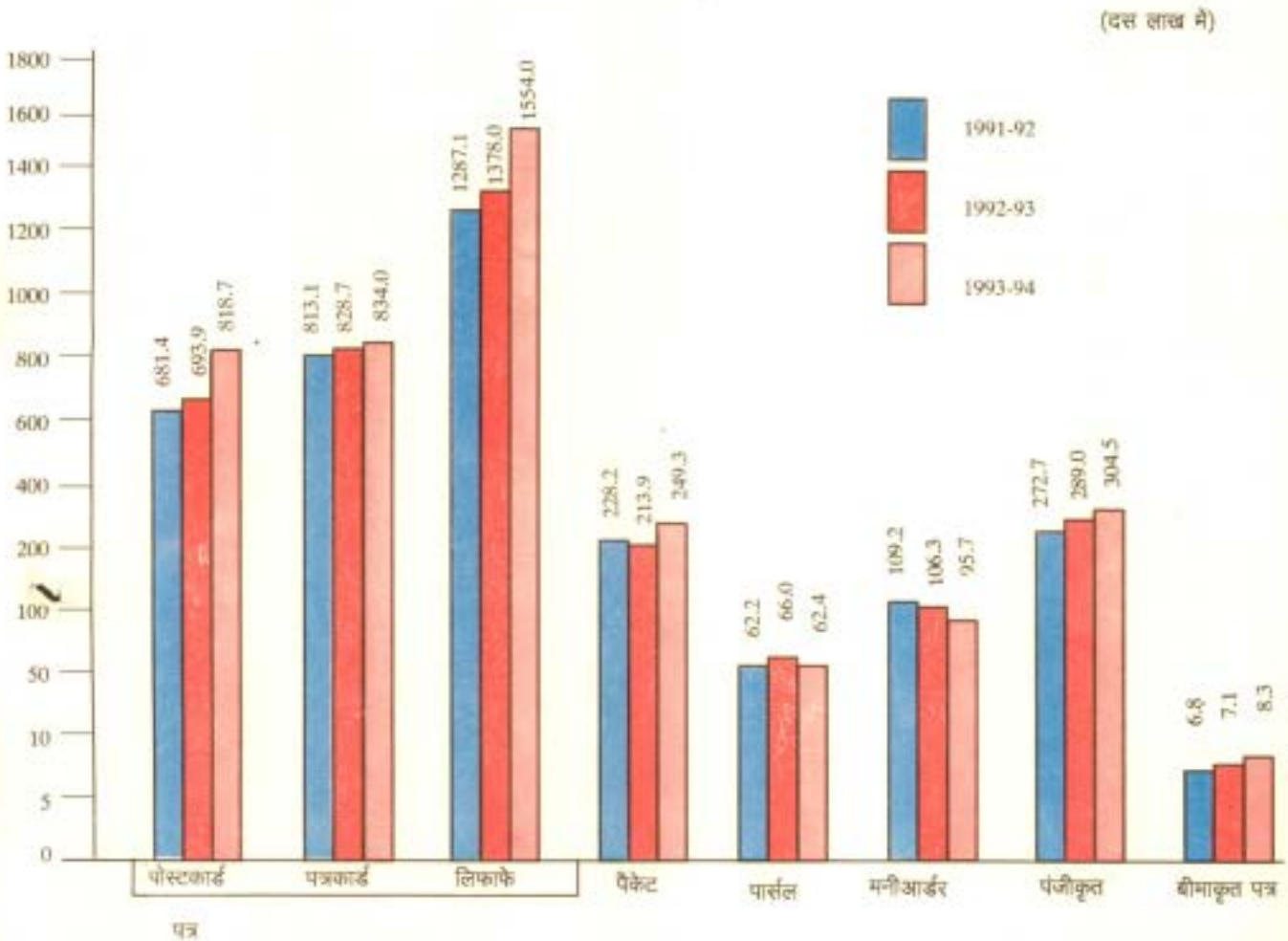

संशोधित करके 3600 और विभागीय उपडाकघरों का लक्ष्य 650 कर दिया गया। आठवीं योजना के संदर्भ में, पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा जनजातीय क्षेत्रों पर, डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए विशेष रूप से बल देने का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान जनजातीय उप योजना के तहत 1500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 1200 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 200 विभागीय उप डाकघर खोलने के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 1302 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और 231 विभागीय उपडाकघरों को मंजूरी प्रदान की गई। वित्तीय दबावों और पदों के सृजन पर प्रतिबंध के कारण वित्त मंत्रालय ने वर्ष 1994-95 के लिए 800 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घरों के प्रस्तावित लक्ष्य को घटाकर 80 कर देने का सुझाव दिया है। अतः 1994-95 के दौरान 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 150 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से 23 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 22 विभागीय उपडाकघर जनजातीय, पहाड़ी, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में खोले जायेंगे।

डाक परिमाण

वर्ष 1993-94 के दौरान निपटाई गई देशी अपंजीकृत डाक परियात की संख्या 3549 मिलियन डाक वस्तुएं थी, जिसमें 3078 मिलियन पत्र थे, 441 मिलियन पैकेट तथा 30 मिलियन पार्सल थे। देसी पंजीकृत डाक की संख्या 334 मिलियन वस्तुएं थी। इस अवधि के दौरान डाक विभाग ने 98.7 मिलियन मनीआर्डरों का पारेषण किया, जिनका कुल मूल्य 31826 मिलियन रुपये था।

स्पीड पोस्ट

डाक विभाग के लिए स्पीड पोस्ट सर्वाधिक लोकप्रिय व राजस्व अर्जित करने वाली सेवाओं में से एक है। इस वर्ष जोधपुर में दिनांक 28.1.1994 को एक नया स्पीड पोस्ट केंद्र खोला गया था जिसे मिलाकर देश में स्पीड पोस्ट केंद्रों की कुल संख्या 63 हो गई।

दिनांक 14.10.93 को 13 अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट संपर्क स्थापित किए गए। इन देशों के नाम हैं :-

बर्मुदा, भूटान, केप वर्डे, अल्सल्वाडोर, आइसलैंड, इस्त्राइल, इटली, केन्या, कुवैत, लातविया, मारीशस, वियतनाम तथा यमन अरब गणतंत्र। इस प्रकार अब कुल 74 देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट संपर्क स्थापित कर लिए गए हैं।

वर्ष 1993-94 के दौरान स्पीड पोस्ट परियात की वृद्धि 47 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान उत्पादित कुल परियात लगभग 1.09 करोड़ वस्तुओं का था। लगभग 50 करोड़ रुपये के राजस्व का अर्जन हुआ, 57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

डाक प्रचालन

भौगोलिक वस्तार तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय डाक प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी डाक-प्रणाली है। इसकी कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के लिए इसका लगातार मानीटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। फील्ड यूनिटों में यह मानीटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। फील्ड यूनिटों में यह मानीटरिंग प्रत्येक स्तर पर की जा रही है। बेहतर सेवायें तथा उपयुक्त मानीटरिंग प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन के अलावा विशेष ध्यान की अपेक्षा रखने वाली डाक की विभिन्न श्रेणियों को विभक्त किया गया है और डाक की छंटाई तथा पारेषण के लिए नए चैनेल आरम्भ किए जा रहे हैं। डाक के इस पृथक-पृथक निपटान से दो लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, पहला यह कि डाक के एक विशेष खंड पर पर्याप्त तथा अनन्य रूप से ध्यान दिया जाएगा ताकि उसके पारेषण व वितरण में तेजी लाई जा सके, दूसरा यह कि इससे अन्य डाक के त्वरित निपटान के लिए परिणामी लाभ होगा।

मेट्रो चैनल

मात्रा तथा समय संवेदनशीलता के संबंध में अंतर्महानगरीय डाक, डाक-परियात की वृहदाकार मात्रा को संघटित करती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बेंगलूर व हैदराबाद के मध्य डाक के निपटान के लिए एक अलग चैनल आरम्भ किया जाए। इसमें इन केंद्रों को प्रेषित पत्रों को प्रारंभिक निपटान चरण में ही अलग-अलग छांट लिया जाएगा। अनेक डाकघरों में ऐसे पत्रों के लिए हलके नीले रंग के लेटर-बॉक्स लगाए जा रहे हैं। ये पत्र विशेष रूप से डिजाइन किए गए थैलों में, जिन पर इनकी सरलतापूर्वक पहचान के लिए विशेष लेबल लगे होंगे, भेजे जायेंगे। इस डाक के निपटान के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए डाक मोटर वाहन तथा स्टाफ का प्रयोग किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो, प्राइवेट विमानों का भी, इन पत्रों को निर्धारित समय तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाएगा। लक्ष्य यह है कि ये सभी पत्र 48 घंटों के भीतर तथा ऐसे अधिकांश पत्र 24 घंटे के भीतर वितरित हो जायें। इस सेवा को 1994-95 में आरम्भ करने का कार्यक्रम है।

राजधानी चैनल

राज्यों की राजधानियों से दिल्ली के लिए और दिल्ली से राज्यों की राजधानियों के लिए भेजे गए पत्र भी डाक के एक महत्वपूर्ण खंड का निर्माण करते हैं। इस चैनल का उद्देश्य ऐसी डाक की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका प्रचालन भी मेट्रो चैनल के प्रचालन जैसा ही होगा। इस सेवा के भी 1994-95 में आरम्भ होने की संभावना है।

बिजनेस चैनल (कारपोरेट डाक)

सरकारी, अर्धसरकारी तथा निगमित निकायों की प्रथम श्रेणी की अपंजीकृत डाक को बिजनेस कारपोरेट डाक के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। यह डाक भी डाक परियात के एक अन्य महत्वपूर्ण खंड का निर्माण करती है। ऐसी डाक वस्तुओं का परियात अत्यधिक है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण शहरों में। चूंकि यह डाक अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है, अतः डाक की छंटाई व पारेषण के लिए समूची व्यवस्था पर यह गंभीर प्रभाव रखती है। अतः बिजनेस चैनल का मूल उद्देश्य ऐसी श्रेणियों की डाक के लिए विशेष प्रबंध करना और इससे भी अधिक यह है कि नियमित कार्य की आकस्मिक अस्तव्यस्तता की अनिश्चितता को समाप्त करना है, ताकि अन्य डाक की छंटाई व पारेषण की प्रक्रिया भी सुचारू बन सके।

बिजनेस डाक, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट किए गए डाकघरों या मेल आफिसों में विशेष काउंटर पर प्राप्त की जाएगी। इस चैनल की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक मुश्त प्रेषितियों के लिए छंटाई चरण में ही पत्रों की अलग-अलग छंटाई करना है। छंटाई, बैगिंग तथा पारेषण, विशेष पहचान द्वारा किया जाएगा जैसा कि मेट्रो चैनल के लिए भी निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सर्किल में एक अधिकारी को परियोजना-समन्वयकर्ता के बतौर नामित किया जाएगा जो इस चैनल के कार्यान्वयन की सूक्ष्म मानीटरिंग करेगा। इस सेवा के भी अगले वर्ष आरम्भ होने की संभावना है।

पंचायत संचार योजना

इस समय जिन क्षेत्रों में मूल डाक संचार सुविधायें सुलभ नहीं हैं, वहां इन सुविधाओं की व्यवस्था करना विभाग का सामाजिक दायित्व है। जनता तथा विभिन्न संसदीय फोरमों की यह मांग है कि इन सुविधायों को प्रदान करने की गति में तेजी लाई जाए। तथापि, एक और डाकघर खोलने में संसाधनों पर दबाव तथा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का यह सुझाव कि डाक प्रणाली के राजस्व खर्च के घाटे की समस्या पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए तथा दूसरी ओर गांवों, विशेषकर ग्रामपंचायतों में मूल डाक सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पंचायत संचार योजना नामक एक वैकल्पिक योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत पंचायत, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और जो विकासात्मक गतिविधि में भी सम्मिलित है, संविदात्मक आधार पर मूल डाक सुविधायें प्रदान करने के लिए नोडल प्वाइंट होगी। पंचायत डाक कार्य निपटाएगी। पंचायत एक कार्यकर्ता का चयन करेगी जो पंचायत संचार योजना का कार्य करेगा, इस व्यक्ति को विभाग द्वारा निर्धारित कमीशन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

मेल मोटर सेवा

वर्ष 1993-94 के दौरान विभागीय मेल मोटर यूनिटों ने 90 स्टेशनों पर कार्य किया। डाक की कार्यकुशलता को कायम रखने के साथ-साथ उसकी कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए और अंततोगत्वा डाक के त्वरित पारेषण के लिए कंडम व पुराने वाहनों के स्थान पर 124 नए वाहन खरीदे गए।

वर्ष 1993-94 के अंत तक मेल मोटर के बेडे में वाहनों की कुल संख्या 1103 थी। वर्ष के दौरान इस बेडे ने 1.95 करोड़ किलोमीटर की कुल दूरी तय की जबकि इस पर कुल 18.94 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसकी औसत लागत 9.69 रुपये प्रति किलोमीटर थी।

डाकघर परिसरों को पट्टे पर देना

हाल ही में विभागीय डाकघरों में उपलब्ध स्थान की एसटीडी/आईएसडी, फैक्स बूथों के संचालन और डाकघर से संबंधित वस्तुओं जैसे बैंकिंग सामग्री, ग्रीटिंग कार्ड आदि बेचने के लिए पट्टे पर देने की एक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को एक ही छत के नीचे डाकघर से संबंधित सभी कार्य निपटाने की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना को कुछ डाकघरों में पहले ही शुरू किया जा चुका है और ग्राहकों द्वारा इसका स्वागत किया गया है।

सभी प्रकार की बचतों, बचत पत्रों सहित बकाया इतिशेष
(दस लाख रु० में)

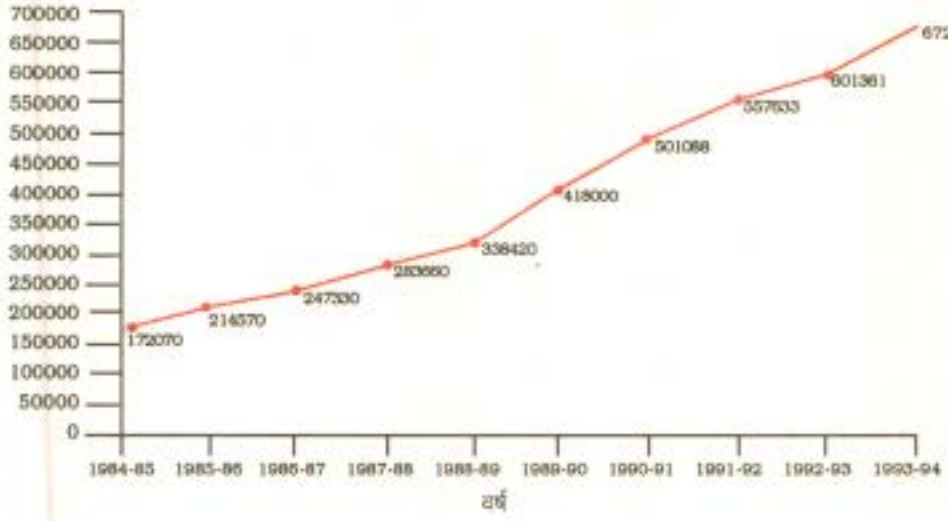

पासपोर्ट आवेदन-पत्र

समूचे देश में 1000 और डाकघरों को विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट आवेदन-पत्र बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ये डाकघर उन 1872 डाकघरों के अलावा हैं जो पहले ही यह सेवा प्रदान कर रहे हैं।

लाइसेंसधारी डाक-टिकट विक्रेता

इस योजना के अंतर्गत एजेंट डाकघर द्वारा विनिर्दिष्ट कमीशन पर डाक-टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचते हैं। कमीशन को 1.5% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अब एक एजेंट अपनी पहल और परिश्रम से आकर्षक पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है।

फिलैटली

दिनांक 1.4.93 से 31.3.94 तक 39 स्मारक/ विशेष डाक टिकट जारी किए गए। इन डाक-टिकटों में "पहाड़ी इंजन" और "पुष्पद वृक्ष" पर चार डाक-टिकटों के दो सेट और सत्यजीत राय पर दो डाक-टिकटों का एक सेट शामिल था।

पूरे देश में 50 फिलैटली ब्यूरो और 199 काउंटरों के माध्यम से डाक-टिकटों की फिलैटलिक बिक्री संचालित की जाती है। 1.4.93 से 31.3.94 तक सात राज्य/सर्किल स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित की गईं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- चण्डीगढ़, पंजाब सर्किल में दिनांक 7.5.93 से 9.5.93 तक फ्पेक्स-93
- देहरादून, उत्तर प्रदेश सर्किल में दिनांक 15.5.93 से 19.5.93 तक अपहिलेक्स-93
- रायपुर, मध्यप्रदेश सर्किल में दिनांक 28.6.93 से 30.6.93 तक मापेक्स-93
- करनाल, हरियाणा सर्किल में दिनांक 17.9.93 से 19.9.93 तक हरपेक्स - 93
- दिल्ली में दिनांक 24.9.93 से 27.9.93 तक डाकियाना-93
- तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु सर्किल में दिनांक 17.9.93 से 20.9.93 तक तेनापेक्स - 93
- विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश सर्किल में दिनांक 16.9.93 से 19.9.93 तक अपेक्स - 93

विभाग ने भारतीय फिलैटलिक कांग्रेस के सहयोग से 25.12.93 से 29.12.93 तक कलकत्ता में राष्ट्रीय प्रदर्शनी "इंपेक्स - 93" का आयोजन किया।

भारतीय डाक-टिकटों के प्रदर्शन और उनकी बिक्री द्वारा विभाग ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लिया:-

- सुबर्या, इंडोनेशिया में 29.5.93 से 4.6.93 तक आयोजित इंडोपेक्स - 93
- बैंकाक, थाइलैंड में 1.10.93 से 10.10.93 तक आयोजित बैंकाक -93

एजेंसी सेवाएं

डाकघर बचत बैंक

वित्त मंत्रालय की ओर से विभाग निम्नलिखित मौजूदा योजनाएं संचालित करता है:-

- बचत खाता योजना
- आवर्ती जमा योजना

आवधिक जमा योजना-1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 3 वर्षीय योजना

- मासिक आय खाता योजना
- लोक भविष्य निधि

कुल पालिसियों की संख्या

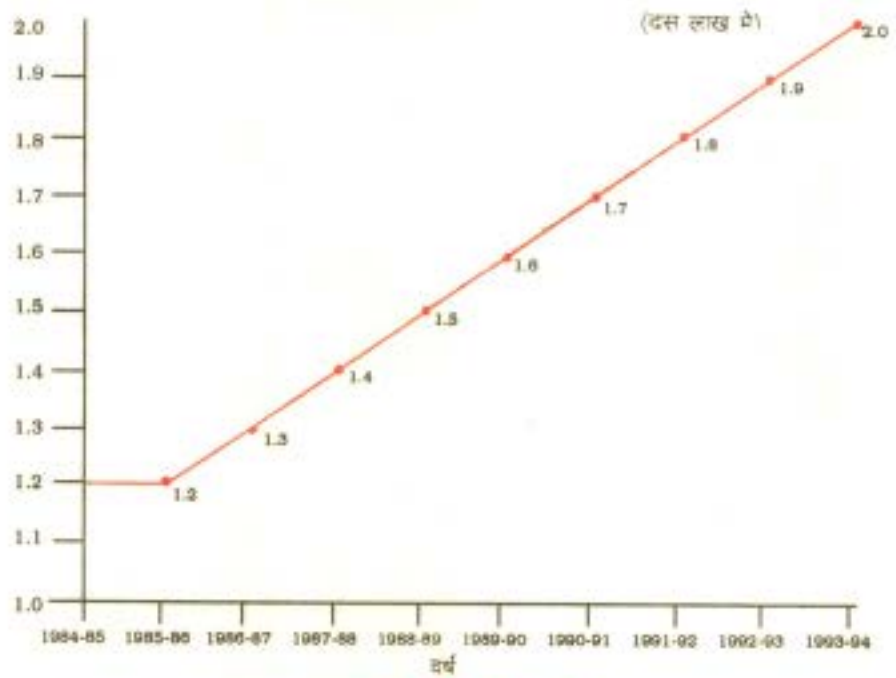

कुल बीमाकृत राशि

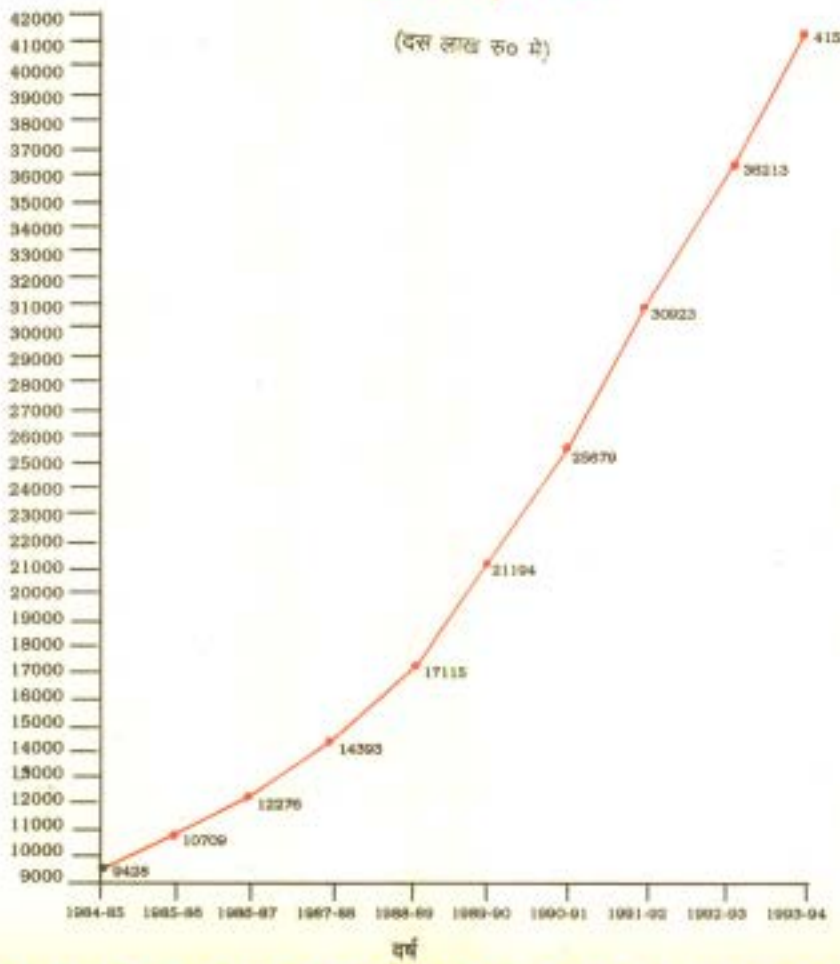

जीवन बीमा निधि (दस लाख रु० में)

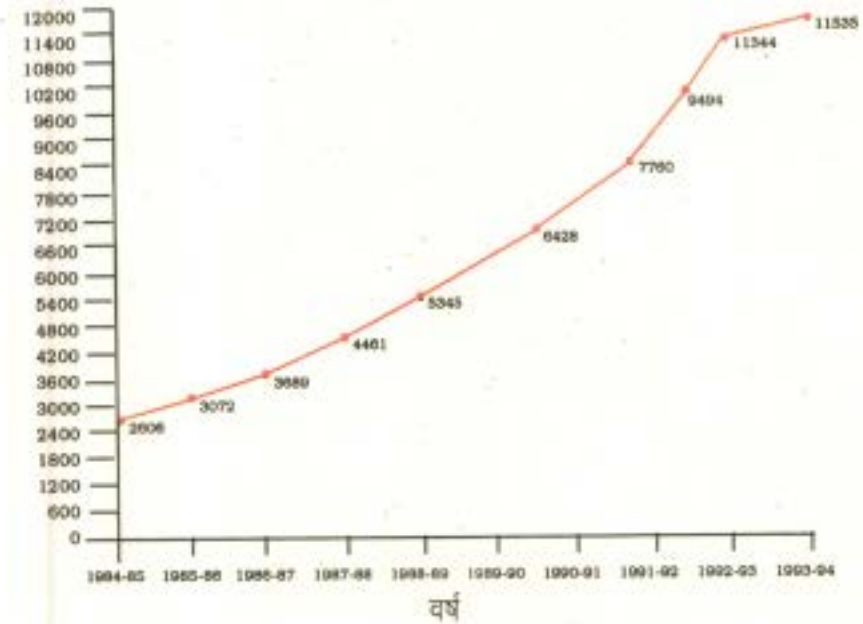

- इंदिरा विकास पत्र
- किसान विकास पत्र
- राष्ट्रीय बचत योजना, 1992

महिला समृद्धि योजना

"महिला समृद्धि योजना"- एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्तूबर, 1993 को यह योजना आरम्भ की गई थी। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के मध्य मितव्ययिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है ताकि वे अपनी बचत का उपयोग विभिन्न घरेलू उद्देश्यों के लिए कर सकें और आवश्यकता के समय उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिल सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 1.32 लाख डाकघरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु की प्रत्येक ग्रामीण महिला 4/- रु० अथवा इसके गुणांकों की प्रारंभिक राशि से निकटतम डाकघर में महिला समृद्धि योजना खाता खोल सकती है, बशर्ते कि अधिकतम जमा राशि 300/- रु० हो। इस जमा राशि पर, जो एक वर्ष तक आवधिक जमा के रूप में रहेगी, 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 75/- रु० होगी।

इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया अर्जित की है। 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 7,29,041 खाते खोले गए जिनमें कुल जमा राशि 9,15,07,250/- रु० थी।

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा चार प्रकार की पालिसियां प्रदान करता है अर्थात् आजीवन बीमा, परिवर्तनीय आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा और प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (20 वर्षीय और 15 वर्षीय)। गैर-चिकित्सा योजना, 1 लाख रु० की अधिकतम बीमित राशि तक उपलब्ध है जबकि चिकित्सा योजना 2 लाख रु० की अधिकतम बीमित राशि तक उपलब्ध है।

वर्ष 1993-94 के दौरान 1.57 लाख नई पालिसियां जारी की गई जिनमें 595.39 करोड़ रु० की राशि बीमाकृत कराई गई थी और वर्ष के अंत तक कुल कारोबार 19,91,723 पालिसियों तक पहुंच गया जिस में वर्ष 1993-94 के अंत तक 4153.36 करोड़ रु० की कुल राशि बीमाकृत कराई गई थी। डाकघर बीमा निधि की शेष राशि जो वर्ष 1992-93 में 1134.4 करोड़ रु० थी, 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 1153.48 करोड़ रु० हो गई। वर्ष 1992-93 के दौरान निपटाए गए 47.26 करोड़ रु० की बीमाकृत राशि के 54307 दावों की तुलना में वर्ष 1993-94 में 60.62 करोड़ रु० की बीमाकृत राशि के 60,644 दावे निपटाए गए और पिछले वर्ष के दौरान अदा किए गए 8.95 करोड़ रु० के ऋणों की तुलना में इस वर्ष 11.42 करोड़ रु० मूल्य के ऋणों का भुगतान किया गया।

वर्ष 1993-94 के दौरान प्रीमियम आय की तुलना में व्ययों का अनुपात 10.48

प्रतिशत था जबकि वर्ष 1992-93 में यह 13.71 प्रतिशत था।

वर्ष 1994-95 के लिए डाक जीवन बीमा कारोबार के लिए 640 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डाक परिसर

वर्ष 1993-94 में डाक, प्रशासनिक और अन्य कार्यालय भवनों के निर्माण पर 33.47 करोड़ रु० खर्च किए गए। विभाग ने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर 11.76 करोड़ रु० भूमि खरीदने/अधिग्रहण के लिए 3.24 करोड़ रु० और इसके डाक प्रशिक्षण केंद्रों और स्टाफ कालेज पर भूमि और भवन संबंधी गतिविधियों पर 34 लाख रु० खर्च किए।

वर्ष के दौरान विभाग ने 111 डाकघरों और अन्य कार्यालय भवनों तथा 236 स्टाफ क्वाटरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। 104 डाकघरों और अन्य कार्यालय भवनों तथा 293 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य भी आरंभ किया गया।

विपणन और वाणिज्यिक प्रचार

भारतीय डाक विभाग पूरी तरह यह महसूस करता है कि वाशिंगटन जनरल एक्शन प्लान के अनुसार, हमारी सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने और उसमें सुधार लाने के साथ-साथ एक सक्रिय विपणन अभियान की भी आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग और उसके कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए। हमारी समष्टि छवि विभिन्न अवसरों पर, जिनमें राष्ट्रीय डाक दिवस भी शामिल है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापनों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है।

वाणिज्यिक प्रचार के क्षेत्र में विभाग ने डाक लेखन-सामग्री पर 160.97 लाख रु० मूल्य के विज्ञापन प्राप्त किए। हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त डाक लेखन-सामग्री पर मुद्रित किए जा रहे ये विज्ञापन सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सुलभ हैं।

पुनः प्रेषण पत्र

वर्ष 1993-94 के दौरान विभाग के 15 पुनः प्रेषण कार्यालयों द्वारा, जो अवितरित डाक पर अंततः कार्रवाई करते हैं, 27.9 मिलियन डाक वस्तुओं का निपटान किया गया। इनमें से 55 प्रतिशत पत्रों के पतों में सुधार करके उन्हें पाने वाले तक पहुंचाया गया, 28 प्रतिशत पत्रों को उनका पता सुनिश्चित करके उनके प्रेषकों को लौटा दिया गया।

प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन

डाक विभाग का मूल कार्य डाक का प्रेषण है। तथापि, एजेंसी, कार्यों के रूप में सीमित बैंकिंग और बीमा कार्यकलापों के अलावा पंजीकृत पार्सलों और मनीआर्डर सेवाओं के रूप में संबद्ध सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से डाक विभाग ने जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने, कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने और प्रौद्योगिकी पर आधारित नई मूल्य वर्धक सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने का संतुलित प्रयास किया है।

मुख्य महानगरों में डाक की छंटाई के मशीनीकरण के लिए बम्बई में आटोमेटिक इंटेग्रेटिड मेल प्रोसेसिंग सिस्टम शुरू करने का एक प्रयास किया गया, जिसने 1.4.1993 से कार्य करना शुरू किया। मद्रास में इसी तरह की प्रणाली को स्थापित करने के लिए आदेश किए जा चुके हैं।

पीसी पर आधारित बहुद्देशीय काउंटर मशीनों की शुरूआत की जनता द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ग्राहक संतुष्टि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस उपस्कर से एक ही काउंटर पर लेखादेय प्रकृति के विभिन्न लेन-देन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कम्प्यूटरीकृत काउंटर के कार्य-क्षेत्र के भीतर और अधिक लेन-देनों को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इससे और अधिक ग्राहक संतुष्टि प्रदान की जा सके। देश के विभिन्न डाक घरों में 1000 और मशीनें उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए गए हैं, जिन्हें मिलाकर ऐसी मशीनों की कुल संख्या 1852 हो जाएगी।

विभाग उपग्रह मनीआर्डर सेवा आरंभ करने पर कार्य कर रहा है। पहले चरण में, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, मनीआर्डर सूचना के पारेषण के लिए विभिन्न राज्यों में 75 माइक्रो अर्थ स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रावधान है। ऐसी आशा की जाती है कि यह सेवा वर्ष 1994-95 में कार्य करना आरंभ कर देगी। इसके परिणामस्वरूप मनीआर्डर सूचना का त्वरित प्रेषण किया जा सकेगा जिससे पूरे देश में मनीआर्डरों का त्वरित वितरण किया जा सकेगा। विभाग इस नेटवर्क का और अधिक मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए भी उपयोग करने की दिशा में विचार कर रहा है।

बचत बैंक प्रचालन के क्षेत्र में दिल्ली में नौ प्रधान डाकघरों, बम्बई में दो प्रधान डाकघरों और चण्डीगढ़ जीपीओ में बचत बैंक कार्य का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। दिल्ली में संसद मार्ग डाकघर में संचयी सावधि जमा और आवर्ती जमा योजनाओं के कार्य का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है और इन्द्रप्रस्थ प्रधान डाकघर में मासिक आय योजना के कार्य का प्रयोगात्मक आधार पर कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। ऑन लाइन सेवाओं पर अधिक ध्यान देकर और अधिक ग्राहक संतुष्टि प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इस वर्ष तक 12 सर्किलों में डाक जीवन बीमा प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका था। इस वर्ष के दौरान एक और सर्किल का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और वर्ष 1994-95 में 6 और सर्किलों को कम्प्यूटरीकृत करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

डाक वित्त

वर्ष 1993-94 का कुल राजस्व 1105.17 करोड़ रु० था जो पिछले वर्ष के 1073.90 करोड़ रु० की तुलना में 31.27 करोड़ रु० (लगभग 2.91%) अधिक था।

गत वर्ष के 1165.71 करोड़ रु० के व्यय और संशोधित प्राक्कलन 1993-94 में दर्शाए गए 1290.00 करोड़ रु० के अनुमानित व्यय की तुलना में इस का कुल कार्यकारी व्यय 1312.26 करोड़ रु० था (अर्थात इसमें करीब 12.57% की वृद्धि हुई)। यह वृद्धि मुख्यतः 16.9.93 से मंजूर की गई अंतरिम सहायता के भुगतान और बोनस आदि के परिलब्धियों की सीमा में वृद्धि के कारण हुई। डाक सेवाओं का राजस्व घाटा 1992-93 के 91.81 करोड़ रु० का तुलना में वर्ष 1993-94 में 207.09 करोड रु० था।

राजस्व और व्यय 1993-94

(वर्ष 1992-93 की तुलना में)

(करोड़ रु० में)

ब्यौरे	1992-93	1993-94	पिछले वर्ष में परिवर्तित प्रतिशत
	राजस्व		
डाक टिकटों की बिक्री	609.75	629.66	3.27
नकद वसूल किया गया डाक शुल्क	268.63	288.26	7.31
मनीआर्डरों, भारतीय पोस्टल आर्डरों	135.68	145.05	6.91
आदि से प्राप्त कमीशन			
अन्य प्राप्तियां	59.84	42.18	29.51
कुल	1073.90	1105.17	2.91
	व्यय		
सामान्य प्रशासन	103.17	114.89	11.36
प्रचालन	1132.23	1288.39	13.79
एजेंसी सेवाएं	62.87	72.96	15.75
अन्य	350.91	390.55	11.30
कुल सकल व्यय	1649.18	1866.79	13.19
कम वसूलियां	483.47	554.53	14.70
निवल व्यय	1165.71	1312.26	12.57

महत्वपूर्ण श्रेणियों का सकल व्यय निम्नानुसार है:-

ब्यौरे	1992-93	1993-94	पिछले वर्ष में परिवर्तित प्रतिशत
वेतन और भत्ते	1246.83	1442.03	15.93
आकस्मिक व्यय और अन्य मदें			
पेंशन संबंधी प्रभार	203.64	227.43	11.68
लेखा एवं लेखा-परीक्षा	37.65	42.49	3.32
डाक टिकट और पोस्टकार्ड आदि	45.77	45.69	0.18
लेखन सामग्री और मुद्रण आदि	18.50	*22.53	43.68
परिसंपत्तियों का रख-रखाव	9.14	*9.24	1.09
मूल्य ह्रास	6.90	8.00	15.94
छुट-पुट कार्य	1.79	1.55	(–) 13.40
डाक की ढुलाई (रेलवे तथा एयर मेल कैरियर का भुगतान)	78.96	67.78	(–) 15.16
कुल	1649.18	1866.79	13.19

★वेतन और भत्तों सहित

पोस्ट-कार्ड

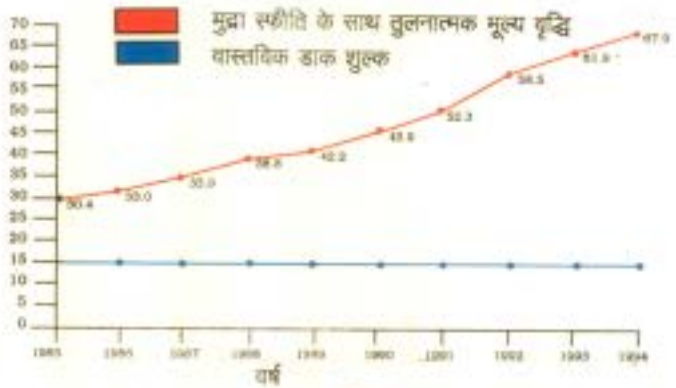

पत्र

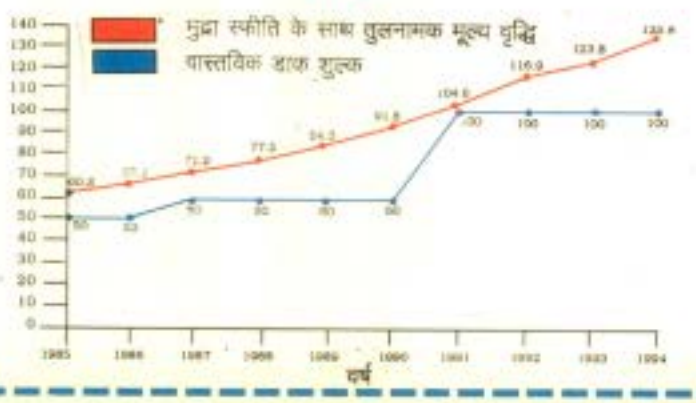

पत्र-कार्ड

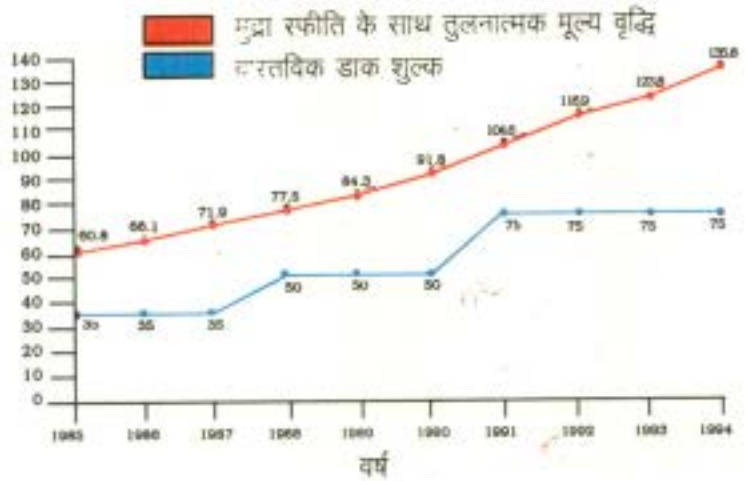

राजस्व और व्यय

(दस लाख रु० में)

सेवाओं की लागत

वर्ष 1993-94 तथा गत वर्ष में मुख्य सेवाओं की लागत एवं राजस्व, नीचे प्रत्येक सेवा के सामने दर्शाए गए हैं:-

(आंकड़े रु० में)

सेवा	1992-93		1993-94	
	लागत	राजस्व	लागत	राजस्व
पोस्टकार्ड	1.54	0.15	1.57	0.15
मुद्रित कार्ड	1.44	0.60	1.46	0.60
लैटर कार्ड	1.57	0.75	1.61	0.75
पत्र	1.78	1.85	1.95	2.13
पार्सल	22.11	17.02	19.40	16.46
मनीआर्डर	14.09	10.97	13.28	11.68
पंजीकरण	10.36	6.00	9.90	6.00
बीमा	13.76	11.01	13.36	14.78
बुक पोस्ट				
बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट	2.28	1.79	2.20	2.07
मुद्रित पुस्तकें	2.94	1.52	2.78	1.56
अन्य	3.27	1.29	3.07	1.52

वर्ष 1993-94 में एजेंसी सेवाओं पर होने वाले कार्यकारी व्यय की विभाग द्वारा वसूली निम्नानुसार थी:-

(करोड़ रु० में)

1.	बचत बैंक और बचत पत्र	:	513.50
2.	सेना पेंशन	:	0.50
3.	कोयला खनिक और ईपीएफ-परिवार पेंशन और विविध सेवाओं का भुगततान	:	6.30
4.	रेलवे पेंशन का भुगतान	:	2.73
5.	डाक जीवन बीमा	:	15.63
6.	सीमा शुल्क वसूली	:	0.82
7.	बचत बैंक युग्मन कार्य	:	0.46
8.	महिला समृद्धि योजना	:	10.00
9.	अन्य	:	0.07
	कुल	:	550.01

पूंजीगत परिव्यय

वर्ष में नियम परिसंपत्तियों पर व्यय 59.25 करोड़ रु० था। इसमे से 82.4% व्यय, भूमि एवं भवनों पर हुआ और 17.6% उपकरणों और संयंत्रों एवं अन्य पर हुआ। वर्ष के अंत तक नियत परिसंपत्ति पर पूंजीगत व्यय 572.48 करोड़ रु० तक बढ़ गया। वर्ष के अंत तक शुद्ध प्रगामी पूंजीगत व्यय के लिए सामान्य राजस्व से 468.59 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता दी गई।

मानव संसाधन

मानव शक्ति

इस विभाग के कार्मिक ही भारतीय डाक प्रणाली के प्रमुख संसाधन रहे हैं। 31.3.94 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 5.98 लाख थी। इनमें से 3.07 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश सेवाएं प्रदान करते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

डाक विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं:-

पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, गाजियाबाद

डाक-तार प्रशिक्षण केंद्र, सहारनपुर

वडोदरा, मैसूर, दरभंगा और मदुरै में स्थित डाक प्रशिक्षण केंद्र।

पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, गाजियाबाद एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, जो डाक विभाग के प्रबंधकीय संवर्गों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस कालेज का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है:-

डाक प्रणाली और अधिक प्रभावशाली और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए कर्मचारियों को अपेक्षित जानकारी और दक्षता प्रदान करना और उन्हें व्यवहार कुशल बनाना। पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रचालन संवर्गों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का संचालन करना।

डाक प्रणाली के प्रबंध के क्षेत्रों में अनुसंधान का दायित्व लेना, और एक डाक आंकड़ा बैंक और दस्तावेज केंद्रों का निर्माण करना।

इसके अतिरिक्त विश्व डाक संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुरोध पर विदेशी प्रशासनों से संबंधित अधिकारियों के लाभ के लिए डाक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। 1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक की अवधि के दौरान पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत द्वारा 6 प्रवेश और 15 सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर 292 अधिकारियों ने, जिनमें 60 विदेशी भी थे, इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया। क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्रों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

अधीक्षकों (डाक और रेल डाक सेवा) और समय मान लिपिकों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना।

डाक और छंटाई सहायकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों, सहायक अधीक्षक, डाकघर, पोस्टमास्टरों आदि को सेवाकालीन पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना, और

मध्य स्तर के प्रबंधकीय पदों पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें उच्च उत्तरदायित्वों को विश्वासपूर्वक निभाने के योग्य बनाना तथा उनमें डाक और रेल डाक सेवा डिवीजनों के प्रबंध को स्वतंत्र रूप से निभाने के लिए आवश्यक समुचित जानकारी और दक्षता विकसित करना।

प्रवेश प्रशिक्षणों के अलावा, आवश्यकता पड़ने पर विदेशी प्रशासनों से संबंधित अधिकारियों के लिए डाक-तार केंद्र, सहारनपुर में पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 31.3.94 को समाप्त अवधि तक सभी पांच प्रशिक्षण केंद्रों में कुल 14,347 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिन्दी माध्यम में प्रशिक्षण देने पर भी विशेष बल दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि और पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन के साथ चलने और विभाग के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन केंद्रों को कम्प्यूटर तथा अन्य प्रशिक्षण उपकरणों, जैसे फिल्म दिखाने के लिए वीडियो रामा प्रोजेक्शन प्रणाली की आपूर्ति भी की गई है।

कर्मचारी संबंध

कर्मचारियों और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की तीन फेडरेशनों और 27 यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ स्वस्थ और सार्थक संबंध बनाए रखने के लिए विभाग प्रयत्नशील रहा। वर्ष के दौरान डाक विभागीय परिषद (जे०सी०एम०) की तीन बैठकें आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान इसकी अपनी समितियों की 20 बैठकें, 8 आवधिक बैठकें, स्थायी समिति की 8 बैठकें और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से संबंधित विभागीय समिति की 2 बैठकें भी आयोजित की गई। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का मैत्रीपूर्ण हल ढूंढना था।

कर्मचारी कल्याण

डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य विभाग के कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं और कल्याण, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित व विकसित करना, उनका आयोजन करना और उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना है। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड को सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। कर्मचारियों के स्वैच्छिक दान तथा खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा धन राशि एकत्र करने की व्यवस्था अधीनस्थ [illegible]ठनों द्वारा की जाती है।

कल्याण बोर्ड की धन राशि, सामुदायिक केंद्रों, मनोरंजन क्लबों, प्राकृतिक आपदाओं के समय दी जाने वाली राहतों, शिक्षा छात्रवृत्तियों, भ्रमण यात्रा, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, शिशु-गृहों, स्कूलों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाओं जैसी

कल्याणकारी गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस वर्ष के दौरान बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 15.35 लाख रु० और भूकंप पीड़ितों के लिए 2 लाख रु० का विशेष आबंटन किया गया।

अवकाश गृह

विभाग अपने कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए 19 स्थानों पर अवकाश गृह चला रहा है।

खेलकूद

वर्ष 1993-94 के दौरान अखिल भारतीय डाक खेलकूद बोर्ड ने इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया- टेबल टेनिस (मध्य प्रदेश), भारोत्तोलन/पावरलिफ्टिंग और सर्वांगीण शारीरिक सौष्ठव (हरियाणा), बैडमिंटन (उड़ीसा), फुटबाल (बिहार), शतरंज (हिमाचल प्रदेश), वालीबॉल (आंध्र प्रदेश), कबड्डी (महाराष्ट्र), एथलेटिक्स और साइक्लिंग (केरल), कुश्ती (पंजाब), बास्केटबॉल (पश्चिम बंगाल), क्रिकेट (राजस्थान) और हाकी (उत्तर प्रदेश) अखिल भारतीय डाक सांस्कृतिक अधिवेशन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया।

दक्षता ब्यूरो

दिनांक 29 और 30 जुलाई, 1993 को सर्किल अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरलों ने भाग लिया। इसके पश्चात् सभी मैट्रो शहरों के डाक योजना प्रचालन के नियंत्रकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इन सम्मेलनों का उद्देश्य डाक के प्रेषण में विलंब कम करना था। महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका उद्देश्य विभाग में दक्षता बढ़ाना और उपभोक्ता संतोष में अधिकाधिक वृद्धि करना था। एस०बी०सी०ओ० में खाता मिलान पर अध्ययन किया गया तथा इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई।

आंतरिक कार्य अध्ययन

निम्नलिखित कार्य अध्ययन संचालित किए गए/पूरे किए गए:

- डाकघरों में राष्ट्रीय बचत पत्र में की गई जमा की निकासी से स्रोत पर कर की कटौती।
- एस०डी०आई०, आर०एम०एस० के पद हेतु मानदंड तैयार करने पर कार्य अध्ययन प्रगति पर है।
- बचत बैंक लेखा रिपोर्ट के द्वारा रेलवे पेंशन के भुगतान से संबंधित पुनरीक्षा अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और एस०आई०यू० ने नए मानदंडों की जांच कर ली है।
- इंदिरा विकास पत्र के विक्रय/इंदिरा विकास पत्र के भुगतान से संबंधित समूह "ग" कर्मचारियों को मंजूर करने के लिए मानदंड बनाने हेतु कार्य अध्ययन।
- इलेक्ट्रॉनिक जोड़ और सूधीकरण यंत्र के लिए मानदंड निश्चित करने हेतु मानदंड बनाने के लिए कार्य अध्ययन।
- स्पीड पोस्ट सेवा से संबंधित समूह "ग" कर्मचारियों के लिए मानदंड बनाना।
- एस० डी० आई०/ए० एस० पी० ओ० सब डिवीजनों को लिपिकीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड बनाना।
- एम०एम०एस० में पर्यवेक्षकीय पदों की मंजूरी से संबंधित कार्य के लिए मानदंड बनाना।
- एस०बी०सी०ओ० में खाता मिलान से संबंधित कार्य के लिए मानदंडों में संशोधन।

उच्चतर कार्यनिष्पादन को मान्यता

विभाग सराहनीय सेवा को हमेशा मान्यता प्रदान करता है। जिन कर्मचारियों की योग्यता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करना अपेक्षित होता है उन्हें मेघदूत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1993-94 में विभाग को अपनी विशिष्ट देन के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और उन्हें मेघदूत पुरस्कार प्रदान किया गया:-

- श्री टी०टी०थॉमस, अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर, केरल सर्किल।
- श्री के०जे० राठौर, अतिरिक्त विभागीय संदेशवाहक, गुजरात सर्किल।
- श्री रहमत अली, पोस्टमैन, राजस्थान सर्किल।
- श्री बी०डी०वत्स, गाइड, पी०ए०, दिल्ली सर्किल।
- श्री जशोबन्त सिंह, छंटाई सहायक, उड़ीसा सर्किल।
- श्री गुलाब सिंह, एस०ए०एस०, हरियाणा सर्किल।
- श्री एम० उमापति, एस०आर०एम०, तमिलनाडु सर्किल।
- श्रीमती मल्लेपल्ली निर्मला, ओ०ए०, आंध्र प्रदेश सर्किल।

राजभाषा को बढ़ावा देना

भारत सरकार की नीति के अनुसार विभाग राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। मुख्यालय और अपने सभी सर्किल कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। यह समय-समय पर इस संबंध में लक्ष्यों और निर्देशों के प्रगामी कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करती है। पुनरीक्षा के दौरान जो कमियां ध्यान में आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन, राजभाषा नीति और सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन की पुनरीक्षा करने के उद्देश्य से विभाग के विभिन्न कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पता लगने वाली कमियों को संबंधित कार्यालयों के ध्यान में लाया जाता है तथा सुझाव दिए जाते हैं। इन उपायों से वांछित प्रगति हुई है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में दिए गए सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति विभाग के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान आवश्यक अनुदेश जारी करती है। इन सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। सर्किल कार्यालयों और अधीनस्थ संगठनों के लिए हिन्दी पुस्तकों की खरीद हेतु सर्किलों को कोष भी प्रदान किए जाते हैं।

राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिकतम

प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग के प्रत्येक सर्किल में वर्ष में कम से कम एक बार "राजभाषा सम्मेलन" का आयोजन करने की योजना शुरू की गई है। क्षेत्र "ग" में स्थित चार सर्किलों में चार राजभाषा सम्मेलन पहले ही आयोजित किए गए हैं। उनके द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुख्यालयों और सर्किलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी अनुदेश भी समय-समय पर जारी किए जाते हैं। विभाग के मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कर कर्मचारियों और अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सरकार की प्रोत्साहन और सद्भाव नीति के द्वारा हिन्दी का कार्यान्वयन समुचित तरीके से करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को सम्मानित करने हेतु उन्हें नकद पुरस्कार देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं।

निरंतर मानीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सचिव (डाक) इस क्षेत्र में व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं ताकि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके।

भाग -2
वार्षिक रिपोर्ट
1994-95

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाएं अच्छी क्वालिटी की हो और उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुकूल हों, डाक विभाग ने 1994-95 में डाक प्रणाली में शीघ्र और समयबद्ध रूप से उचित, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु अनेक अनुकूल कदम उठाए। अपेक्षाकृत शीघ्र और अधिक विश्वसनीय तथा अनुकूल सेवाओं की मांग पूरी करने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित नई सेवाएं शुरू करने के लिए कई उपाय किए गए। मौजूदा वर्ष में किए गए सभी कार्यों का मूल उद्देश्य डाक प्रणाली को वास्तव में आधुनिक, विश्वस्तरीय संगठन में परिवर्तित करना है जो अपने उपभोक्ताओं की मौजूदा और आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

डाक प्रचालन

उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करने के लिए डाक को अलग-अलग कर दिया गया है। मेट्रो चैनल, 2.4.1994 को शुरू किया गया है। इसमें मेट्रो शहरों के बीच पिनकोड अंकित डाक की समयबद्ध प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह राजधानी चैनल 16.5.1994 से शुरू किया गया है। इसमें राज्य की राजधानियों और नई दिल्ली के बीच पिनकोड अंकित डाक की शीघ्र प्रक्रिया की जाती है। बिजनेस चैनल 1.7.1994 से शुरू किया गया है। इसमें एक समय-सीमा के भीतर बिजनेस डाक की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है।

एक्सप्रेस पार्सल सेवा (ई०पी०एस०) 1.12.1994 से शुरू की गई है। इसमें दिल्ली- बंबई, दिल्ली-कलकत्ता और दिल्ली-मद्रास के बीच दोनों ओर से एक विश्वसनीय और समयबद्ध सेवा प्रदान की जाती है। दिनांक 15.11.1994 से स्पीड पोस्ट के राष्ट्रीय नेटवर्क में 56 ए०पी०ओ० और 99 ए०पी०ओ० शामिल किए गए हैं।

समष्टि योजना

डाक विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से डाक प्रणाली को आधुनिक बनाना है तथा उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत तीव्र और दक्ष सेवा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई नई सेवाओं की शुरूआत करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत अधिक संकेंद्रित तरीके से प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने और इनका दर्जा बढ़ाने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने पर बल दिया गया है ताकि अपेक्षाकृत अधिक दक्ष और अनुकूल उपभोक्ता सेवा सुनिश्चित की जा सके; अनुकूल, स्वच्छ और आधुनिक कार्य वातावरण के द्वारा कर्मचारी संतोष बढ़ाया जा सके तथा उपभोक्ता आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नई मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान की जा सकें।

मौजूदा वर्ष के दौरान 53 चुनिंदा महत्वपूर्ण डाकघरों में काउंटर सेवाओं और अन्य फ्रंट ऑफिस कार्यों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह आधुनिकीकरण कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों पर केंद्रित है। इन काउंटर मशीनों की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है। ये काउंटर मशीनें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके काउंटर कार्यों का स्तर बढ़ाती हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को दक्ष, अनुकूल और सरल-सहज सेवा प्रदान करना और उन्नत कार्य परिवेश के द्वारा कर्मचारी संतोष में वृद्धि करना है। वर्ष 1994-95 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 53 चुनिंदा महत्वपूर्ण डाकघरों का पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले आधुनिक फुटकर डाकघर, शहरी केंद्रों में दक्ष और सुसंगत सेवाएं प्रदान करेंगे। जहां व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्यकलाप को प्रोत्साहित करने और उन्हें कायम रखने के लिए डाक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार अलग-अलग डाक छंटाई और वितरण की नई योजना अपेक्षाकृत अधिक समय-संवेदनशील डाक का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करेगी। इन उपायों से डाक की संकुलता दूर करने में सहायता मिलेगी जिससे अन्य डाक के निपटान में सुधार होगा। बाह्य यूनिटों में प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग ने आधुनिक प्रचालनात्मक उपस्कर प्रदान करने का एक कार्यक्रम बनाया है जिससे डाक प्रचालनों से नीरसता दूर करने में सहायता मिलेगी। 1994-95 के दौरान इस योजना के तहत 100 प्रचालनात्मक डाकघरों को इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने का लक्ष्य है।

चालू वर्ष में मुख्यतः अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और केंद्रीभूत प्रबंधन के द्वारा कार्य वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार लाने और उपभोक्ता संतुष्टि में इसके अनुरूप वृद्धि करने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर प्रबंधन के द्वारा

सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश के प्रत्येक डाक डिवीजन में 10 प्रचालनात्मक डाकघरों को चुना गया है।

विभाग की स्वीकृत योजना स्कीमों में से एक स्कीम यह है कि जिस गांव की जनसंख्या 500 से अधिक है और जिसमें अभी तक यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है, ऐसे प्रत्येक गांव में लेटर-बॉक्स सुविधा प्रदान की जाए। इस संबंध में विभाग का उद्देश्य है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान यह लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया जाए। 31.3.94 की स्थिति के अनुसार यह आकलित किया गया था कि ऐसे गांवों की संख्या 71,075 है जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है और जिनमें लेटर बॉक्स प्रदान नहीं किया गया है। प्रस्ताव है कि 31.3.95 तक 51,327 गांवों में यह सुविधा प्रदान की जाए।

उपग्रह मनीआर्डर

मनीआर्डर के प्रेषण में तेजी लाने और इस प्रकार इस सेक्शन को और अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उपग्रह मनीआर्डर सेवा के पहले चरण में देश के 75 स्थानों पर सूक्ष्म-भू स्टेशनों के संस्थापन की योजना है जिनमें से प्रत्येक स्टेशनों में वी०एस०ए०टी० (वेरी स्मॉल कम्प्यूटर एपर्चर टर्मिनल) और अन्य कम्प्यूटर यंत्र लगाए जाएंगे। 1994-95 में 6 स्थानों -- दिल्ली, मद्रास, बेंगलूर, लखनऊ, पटना और शिमला में शुरू में एक पायलट परियोजना शुरू की गई। दिनांक 16.12.1994 को यह प्रणाली माननीय प्रधानमंत्री श्री पी०वी०नरसिम्हा राव द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। मौजूदा वर्ष के दौरान ऐसे 20 और स्टेशनों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इस नेटवर्क से मनीआर्डर प्रेषण में तेजी आएगी और अंततः मनीआर्डरों का अत्यन्त तीव्रतर वितरण होगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी की रचना वी०एस०ए०टी० नेटवर्क के द्वारा तीव्र डाटा प्रेषण के लिए एक नेटवर्क प्रदान करती है। विभाग नई मूल्यवर्धित सेवाएं भी शुरू कर रहा है जिससे विशेष रूप से मूल पाठ और डाटा के शीघ्र और विश्वसनीय प्रेषण की उपभोक्ता आवश्यकताएं पूरी होती है।

हाइब्रिड मेल सेवा

हाइब्रिड मेल उपग्रह चैनल के माध्यम से सामग्री प्रेषण के लिए एक नई सेवा है। इसमें वी०एस०ए०टी० नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है तथा चाहे पोस्टमैन या मुद्रित फार्मेट में या एक फ्लॉपी के द्वारा प्रेषिती को सामग्री प्रेषित की जाती है। हाइब्रिड मेल सेवा के द्वारा कोई सामग्री, चाहे वह कितनी भी बड़ी-छोटी हो, कम्प्यूटरों के प्रयोग द्वारा उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से तत्काल प्रेषित की जा सकती है। उपभोक्ताओं को यह सामग्री फ्लॉपी पर लाने का विकल्प होगा, अन्यथा उन्हें उस डाकघर में कम्प्यूटर सुविधा प्रदान की जाएगी जहां से यह बुकिंग की गई है। प्राप्ति स्टेशन पर उन्हें अपने कम्प्यूटर के डाटा डाउनलोड करने का विकल्प प्राप्त होगा बशर्ते कि वे एक मोडेम और एक टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हों। अन्यथा मुद्रित संदेश चाहे उनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या उनके परिसर में इसे वितरित किया जा सकता है। इस सेवा का उद्घाटन माननीय संचार राज्य मंत्री श्री सुखराम ने 14.1.95 को किया। तीव्र नकद स्थानान्तरण और ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए विशेष रूप से समष्टि क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं तैयार की जा रही हैं और उन्हें शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उपभोक्ता संतुष्टि के लिए विभाग की तीव्र जागरूकता को ध्यान में रखते हुए व्यस्त शहरीय केंद्रों में स्थित प्रमुख डाकघरों में पोस्ट-शॉप खोली जा रही है जिन्हें निजी मालिकों द्वारा चलाया जाता है। इन पोस्ट शॉप में उपभोक्ताओं को अक्सर वे विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं जो पैकेज, पार्सल और पत्र तैयार करने में अपेक्षित होती हैं। इनके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिए अन्य उपयोगी वस्तुओं के साथ-साथ आई०एस०डी०- एस०टी०डी० सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं।

काउंटर मशीनीकरण

यह योजना प्रतीक्षा समय कम करते हुए डाकघर में एक ही खिड़की पर बचत बैंक सहित बहुत सी डाक सुविधाओं की सुविधा प्रदान करता है। पी०सी० आधारित बहुद्देशीय काउंटर मशीनें और अधिक संख्या में उपलब्ध कराने के ऑर्डर दे दिए गए हैं जिससे इन मशीनों की कुल संख्या 1852 हो जाएगी। नवम्बर, 1994 तक 1060 मशीनें लगाई जा चुकी हैं। शेष मशीनें लगाई जा रही हैं। अपेक्षाकृत अधिक दक्ष और अनुकूल काउंटर सेवाएं प्रदान करने के लिए, मशीनों के लाभों के प्रति आशान्वित होकर चुनिंदा महत्वपूर्ण डाकघरों का पूरी तरह आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

यांत्रिक उपस्कर का प्रयोग

डाक वस्तुओं पर बेहतर मुहर छाप के लिए डाकघरों को और अधिक डाक-टिकट विरूपण मशीनों और अच्छी क्वालिटी की हस्त-मुहरों की आपूर्ति करने के प्रयास जारी हैं। 270 डाक-टिकट विरूपण मशीनें उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं जिनमें से 180 मशीनों की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है और शेष मशीनों की आपूर्ति मार्च, 1995 तक कर दिये जाने की संभावना है। इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री, कलकत्ता को 25,000 हस्त-मुहरों का निर्माण करने के आदेश दिए गए थे जिनमें से इसने 11,000 हस्त मुहरों की आपूर्ति कर दी है।

डाक नेटवर्क का विस्तार

इस वार्षिक योजना के दौरान 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 150 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है जिनमें से डाकघर खोलने के लिए

31.12.1994 तक 56 प्रस्तावों की प्रक्रिया चल रही थी।

पंचायत नेटवर्क का प्रयोग करते हुए ठेके के आधार पर गांवों में मूल डाक सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभाग ने "पंचायत संचार सेवा योजना" नामक एक नई योजना तैयार की है। चालू वर्ष के दौरान इस योजना का उद्घाटन किए जाने का कार्यक्रम है।

फिलैटली

1.4.94 से 31.12.94 तक चौबीस स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए जा चुके हैं। इन डाक-टिकटों में शामिल हैं-चलचित्र सिनेमा के आचार्य सत्यजीत राय, महात्मा गांधी की 125 वीं वर्षगांठ और बड़ौदा संग्रहालय का शताब्दी समारोह। विभाग ने दो अंतर्राष्ट्रीय डाक-टिकट प्रदर्शनियों में भाग लिया- 31.8.94 से 4.9.94 तक सिंगापुर में सिंगापेक्स - 94 और 16.8.94 से 25.8.94 तक सिओल में फिला-कोरिया-1994। दिनांक 31.12.1994 तक निम्नलिखित चार राज्य स्तरीय फिलैटली प्रदर्शनियां आयोजित की गई - पटना में बाईपेक्स-1994, बैंगलूर में कर्नापेक्स-1994, अहमदाबाद में गुजपेक्स -1994 और बंबई में महापेक्स-1994

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

22 अगस्त से 14 सितम्बर, 1994 तक सिओल, कोरिया गणराज्य में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 21 वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री सुखराम, संचार राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में भारत को प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद में निर्वाचित किया गया। इसके अतिरिक्त भारत को पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रशासन परिषद की वित्त समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। भारत प्रशासन परिषद के नैतिक योजना कार्य दल का भी सदस्य है।

जून- जुलाई, 1994 में सर्फर्स पैराडाइज, आस्ट्रेलिया में एशियाई प्रशान्त डाक संघ कार्यकारी परिषद् और एशियाई प्रशान्त डाक प्रशिक्षण केंद्र के वार्षिक सत्र आयोजित किए गए। सचिव (डाक) के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोपरेशन (सार्क)

डाक विभाग ने 4 और 5 मई, 1994 को नई दिल्ली में संचार पर सार्क तकनीकी समिति की दूसरी बैठक की मेजबानी की। सभी सार्क देशों के प्रतिभागियों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में क्षेत्र में डाक व दूरसंचार में प्रोत्साहन और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सचिव (डाक) जुलाई, 1994 में ढाका में आयोजित सार्क स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए और संचार पर सार्क तकनीकी समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

द्विपक्षी सहयोग

इजराइल का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल संचार, विज्ञान और कला मंत्री के नेतृत्व में 27.11.94 से 1.12.94 तक भारत का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान दूरसंचार और डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

डाक सेवाओं में काउंटर प्रचालन का आधुनिकीकरण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट आव सेल (ई०पी०ओ०एस०) में आस्ट्रेलिया की सुविज्ञता को आपस में आदान-प्रदान करने हेतु अक्तूबर 1994 में प्रबंध निदेशक, आस्ट्रेलिया डाक सहयोग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

पुनःस्थापन योग्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

पर्यावरण संरक्षण के एक उपाय के रूप में विभाग पुनः स्थापन योग्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के प्रयास कर रहा है। ग्रामीण डाकघरों में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए फोटोवोल्टेक उपस्कर के माध्यम से सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु एक पायलट परियोजना बनाई गई है जिसमें देश के दस चुनिंदा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सहयोग से यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

सर्किल अध्यक्षों का सम्मेलन

15 और 16 जुलाई, 1994 को दो दिनों के लिए नई दिल्ली में सर्किलों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। विचार - विमर्श में डाक सेवाओं और प्रौद्योगिकी के प्रयोग में उत्कृष्टता लाने के तरीकों और साधनों की जांच करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया।

महिला समृद्धि योजना

इस नई योजना में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास और स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया है। यह योजना अत्यन्त लोकप्रिय हुई। 31.12.1994 तक 72, 04, 193 खाते खोले गए और 65,90,20,356 रुपये की रकम जमा की गई।

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा पहले केवल डाक कर्मियों के लिए शुरू की गई थी जो बाद में सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारियों को भी दी गई। अब इसका विस्तार ग्रामीण जनता तक भी किया जाता है। यह योजना तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही इसे शुरू किये जाने की संभावना है।

राजभाषा

दैनिक सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सचिव, डाक विभाग ने 13 जुलाई, 1994 और 16

अगस्त, 1994 को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दो बैठकें कीं तथा विभाग में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की।

14 से 28 सितंबर, 1994 तक विभाग और इसके अधीनस्थ संघटनों ने हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

14 सितम्बर, 94 को हिन्दी दिवस के अवसर पर सचिव (डाक) ने संघ की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों को संबोधित किया।

राजभाषा की प्रगति के लिए संविधान में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में पर्यवेक्षकीय अधिकारियों के योगदान हेतु 29.11.94 को इन अधिकारियों की एक विशेष बैठक/कार्यशाला का आयोजन किया गया।

केबल टी०वी० नेटवर्क के आपरेटरों का पंजीकरण

सितंबर, 1994 से प्रधान डाकघरों के प्रभारी हेड पोस्टमास्टरों को उनके लेखा अधिकारक्षेत्र में केबल टी० वी० आपरेटरों के पंजीकरण प्राधिकारी के बतौर प्राधिकृत किया गया है। समूचे देश में जनवरी, 1995 के अंत तक 4485 पंजीकरण किए जा चुके हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित लेखा परीक्षा

डाक सेवा बोर्ड

इस वर्ष डाक सेवा बोर्ड में भी अनेक परिवर्तन हुए। अब बोर्ड में श्री एस०सी०महालिक अध्यक्ष हैं। सर्वश्री पी० के० बागची, ए०वी०राव और सी०जे०मैथ्यू सदस्य हैं। वरिष्ठ उप महानिदेशक (गुणवत्ता प्रबंध) श्री के०धीश, सचिव, डाक सेवा बोर्ड भी हैं।

पैरों का विवरण तथा दिनांक 20.1.95 की स्थिति के अनुसार बकाया

लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या तथा वर्ष	पैरा	विषय
1. 1994 का 7	1.9	एजेंसी कार्य
2. 1994 का 7	1.10	वित्त लेखा
3. 1994 का 7	1.11	सार्वजनिक खातों में से अग्रिम
4. 1994 का 7	3.1	पोस्टल स्टाफ कालेज तथा डाक प्रशिक्षण केंद्र
5. 1994 का 7	3.2	आंतरिक जांच संगठन
6. 1994 का 7	4.1	डिडस्टिंग प्लांटस के लिए योजना का कार्यान्वयन न होना
7. 1994 का 7	4.2	नागपुर में खाली स्टाफ क्वार्टर
8. 1994 का 7	4.3	बचे हुए कागज को बदलने के लिए एक मशीन की अधिप्राप्ति में विलम्ब

पैरा 1.10, 1.11, 3.1, 3.2, 4.2 से संबंधित की गई कार्रवाई की टिप्पणी पहले ही जांच के लिए लेखा-परीक्षा को भेज दी गई है।

PART-1
ANNUAL REPORT
1993-94

OVERVIEW

The four pillars of the Postal system of India are its universality, statutory protection of several constituent services, Parliamentary regulation of rates and reasonable liability for mail or remittance. The growth of the network to 1,52,786 Post Offices, 89% of them in villages, the greater part of which has taken place since Independence, is one unmistakable indication of the mission that it has borne laboriously; one Post Office for 23.12 sq. km. of rural land and 3.16 sq. km. of urban stretch, or 4,612 people in villages and 12, 924 people in a town or city, was achieved under severe strain of resources and effort. That, regardless of terrain and sparseness of mail, every address-site everywhere in the country is served by a delivery-hand everyday when there is mail for someone there, is both unparalleled in the world, and hard to maintain. That the mail services in the country are the lowest-priced among all countries confirms the highest concerns it attaches to the value of mail to the sender and to the addressee alike. In 1993-94, 3549 million unregistered postal articles and 334 million registered postal articles of domestic origin were delivered in the country, which was 294 million and 20 million respectively more than that of the previous year, representing an average of 8.8% increase. The Post also carried 98.7 million money orders of a total value of Rs.31,826 million. While the number of money orders fell by 6.6 million or 6.3%, value rose by Rs.2,702 million or 9%. International mail is still another dimension, both in numbers and in diversity of origin. Per capita, these numbers do not indicate a status of comparable volume with countries like the USA or Japan, but that, by itself, proves the magnitude of the task in processing and delivery of mail, so far between and so few. Processing and transmission of mail over a very vast and complex network is no small a matter, whether in its organisation or in actual work, not to speak of the possible aggregate of address-sites that lie congested or scattered, as the case may be.

Urban Challenges & Automation

Six cities namely Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Bangalore and Hyderabad, with a total population of 35.57 million, account for 7 million articles of originating domestic mail each day representing around 59% of the country's mail traffic as a whole. There is a great disparity in mail intensity between these metros on the one hand and the rest of India on the other and poses a major challenge to the system in the former. The time constraints at the processing centres that arise from these volumes are a serious fact to reckon with in mail movement without delay, at current times, and only to become more seroius in the times ahead with galloping metropolitan mail growth rate because of wide-ranging economic activity. There are limits to concerted manual applications, even with the best of devotion. This realisation came upon the Department a few years ago, and from the consummate planning and calculated programming that followed was born the country's first Automated Mail Processing Centre at Bombay in April, 1993 that is capable of processing 1.2 million letters in a 24 hours work-day. It is slowly proving its role in solving the city's teeming operational problems. The second, an identical assembly, is coming up in Madras for commissioning in September, 1995. The two together cost Rs.39.7 million. They convey a visible message for the future, that conventional arrangements do not hold good everywhere.

Automation is more than technology, a culture. The Post has accepted it congenially, beyond the internal work that mail processing is in its external face with the customers. In early 1991, 22 Post Offices in 7 cities, Bombay, Delhi, Madras, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Lucknow became fore-runners of automation in counter work providing speed and combining multiple services at one window. That was an instant success and led to the momentous decision to automate counters on a large scale. 657 Post Offices by now have or will have by March, 1995 automated counters. Each such counter accepts registered, insured and value payable letters and parcels, speed post articles, money orders etc. and can handle a transaction in one minute. Long queues that characterised hard-pressed urban post offices are thereby becoming a thing of the past and India is well on its way to the goal of five minutes to the last man on the line.

A longer step further that it is, 15 Post Offices in the country have fully automated counter services by now except for sale of stamps and this number will grow to 53 by March, 1995.

In these automation measures for the counter services, Department has spent Rs.85 million in 1993-94 and 1994-95 together. In addition, there is automation of Postal Life Insurance accounting and Post Office Savings Bank, bringing about a total change in

the work process.

The total outlay on automation in 1994-95 is estimated to be Rs.390.30 million to be followed by Rs.481.60 million in 1995-96. Next year, 500 more Post Offices will have fully automated services. In the final assessment, the customer care that it will enhance, is beyond arithmetical estimation.

Finances and Pricing - Need for a Comprehensive Approach

The finances of the Post continue to be in minus. In 1993-94, despite an increase in revenue of Rs.312.7 million over the previous year, deficit increased to Rs.2,070.9 million from the previous year's Rs.918.10 million raising issues of prime importance for the Post and the country. With rates staying far behind the rise in costs and costs increasing relentlessly, deficits have become an annual feature.

Deficit is not seemingly a matter of balancing both sides of the ledger. There is the unequivocal demand from the users for excellent service which comes only in part from human performance and to a greater extent from investments for infrastructural support - better premises, ergonomic work facilities, efficient equipment, transportation support and the like. Deficits are cramping investment and thereby hamper quality of service.

There are paradoxical indications from the revenue statistics of 1993-94, in the just 2.91% increase over the previous year while mail volume increased by 8.8%. One conclusion could be that mail volumes have increased largely in the highly subsidised sectors like Letter Card, Post Card, Newspaper, subsidies being as much as 32.52%, 89.57% and 92.03% respectively. Steep increase in the use of Post Card for commercial purposes like television competitions is one such factor. The social purpose of the Post gets gradually eroded thereby. This is an aspect for close analysis and a socially prudent rates policy.

The Post needs extensive support from all quarters for fulfilling its present and future role as essential infrastructure for social and economic growth. It needs an appropriate legal status, financial and management flexibility in consonance with its emerging business orientation.

India Post and the Future

Customer care is the constant watchword for the Post internationally, as promoted by the Universal Postal Union in the General Debate of the Washington Congress in 1989 and repeated by the Seoul Congress in 1994. Everywhere, the Post is changing. In India, the many steps that have been taken and the many more that are contemplated are oriented towards it. A society with state-of-art communication must be the goal, coming as it will, from new legislation, commercial impetus, financial re-orientation, structural changes and whole-hearted staff support, the Indian Postal System will compete with the best in the world. Those within look forward to the unfolding changes so that the Post in the 21st century is not inferior to anything else in the century.

ORGANISATION

As a Department of the Ministry of Communications, the Department of Post was created in January, 1985. During the year under review, the Department continued to function under Shri Sukh Ram, Minister of State for Communications (Independent Charge).

Headquarters

The management of the Department vests in the Postal Services Board. The Chairman of the Board is also the Secretary, Department of Post and the Director General, Post. There are three Members of the Board, holding the portfolios of Operations, Development and Personnel. In addition, there is a Financial Adviser.

The Board is assisted by a Secretary, who is also Sr. Dy. Director General (Quality Management). The Board directs and supervises the management of the Postal Services in the country with the assistance of eighteen Deputy Directors General in the Directorate General of Post.

Circles

The Department's operational responsibilities are borne by nineteen Postal Circles. A Circle comprises, one or more State/Union Territories and is headed by a Chief Postmaster General and is generally divided into Regions comprising a group of field units called Divisions. Each Region has a Postmaster General and provides high level management support to the Chief Postmaster General in the field.

In addition to the Circles, there are Regional Mail Planning Units at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras under Controllers of the rank of Postmaster General. The controllers bring exclusive professionalism to the planning and control of mail operations. There are also other functional Divisions and Units like Mails Division, Stores Depot, Stamps Depot and Mail Motor Service in a Circle.

Indian Post Offices are categorised as Head, Sub and Branch Post Offices. Branch Post Offices are usually Extra-Departmental Post Offices located in rural areas. Most of the Sub Post Offices are departmental, and are located in both rural and urban areas. Head Post Offices are graded into five categories according to their workload and staff strength, the biggest being the General Post Offices of Bombay and Calcutta, followed by the GPOs at Madras, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Kanpur, Lucknow and other major cities of the country.

The Army Postal Service is headed by a Major General. He is designated as Additional Director General, APS, and is also described as Chief Postmaster General, APS Circle. Most of the personnel in the officers cadre as well as other ranks, including the Major General, are drawn from the civil postal service.

Positions

On 1.4.94, the Postal Services Board consisted of Shri T.E. Raman, Secretary (Post), Director General, Post and Chairman, Postal Services Board, Shri B.Parabrahmam Member (Personnel), Shri S.C.Mahalik, Member (Operations). Shri G.S.Rajamani, as Joint Secretary and Financial Adviser, Department of Post, is a permanent invitee to the Board. Shri K.A.Abrol was Sr. DDG and Secretary of the Postal Services Board. Currently, Shri S.C. Mahalik is the Chairman of the Postal Services Board, Shri P.K.Bagchi is Member (Development), Shri A.V.Rao is Member (Personnel), Shri C.J.Mathew is Member (Operations) and Shri K.Diesh is Sr. DDG and Secretary, PSB.

International Relations

The Annual Session of the Universal Postal Union Executive Council and the Consultative Council for Postal Studies were held in April and October, 1993 respectively at Berne, Switzerand. A delegation comprising of senior officers of the Department led by Secretary (Post) represented India at these sessions. India was associated closely with the Working Party on Terminal Dues and Restructuring of the UPU. In addition to chairing an important committee of the CCPS on "Postal Development", India submitted the report on two important UPU studies relating to "Improvement of Rural Postal Services in Developing Countries" and "New Product Development". India was the reporting country for these important studies. An Indian delegation attended the meeting of the Asian Pacific Postal Union Executive Council and the meeting of the Governing Board of the Asian Pacific Postal Training Centre held at Kobe, Japan in September, 1993. India hosted the First Meeting of the SAARC countries during the year. The Indian Postal Administration organised a Workshop on "Mechanisation of Postal Services" for officers of the SAARC Postal Administrations at the Postal Staff College, Ghaziabad. Participants from Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan and India participated in this workshop.

A meeting of the Indo-Chinese Working Group on Post was held in India in November, 1993.

POSTAL OPERATIONS

Introduction

Postal operations, normally perceived as a singular function exclusively to deliver letters, is infact a chain of multifarious inter-related functions such as collection, sorting, transmission, final sorting at destination and delivery. In addition there are ancillary activities for special services like registration, money order, speed post, postal orders. Success of this multiplicity of operations so as to give optimum customer satisfaction is dependant on efficiency of other agencies like Airlines, Railways, Roadways and Shipping. Apart from mail communication system, the Department of Post also performs some functions on behalf of other Ministries and Departments. Such services like the Savings Bank and Postal Life Insurance are known as agency functions.

Expansion of Postal Network

In terms of the number of post offices, India ranks foremost among the postal systems of the world. This is attributable as much to the vastness of the country and its large population as to the conscientious effort made by Government since independence to develop the postal network as a means of social integration, an instrument of economic development and rural regeneration. Apart from serving the basic purpose of extending postal communications, the expansion of postal services has also significantly contributed to the achievement of socio-economic goals of the Government such as spread of literacy, generation of employment, promotion of small savings and establishment of industries in backward and far flung areas.

Number of Post Offices

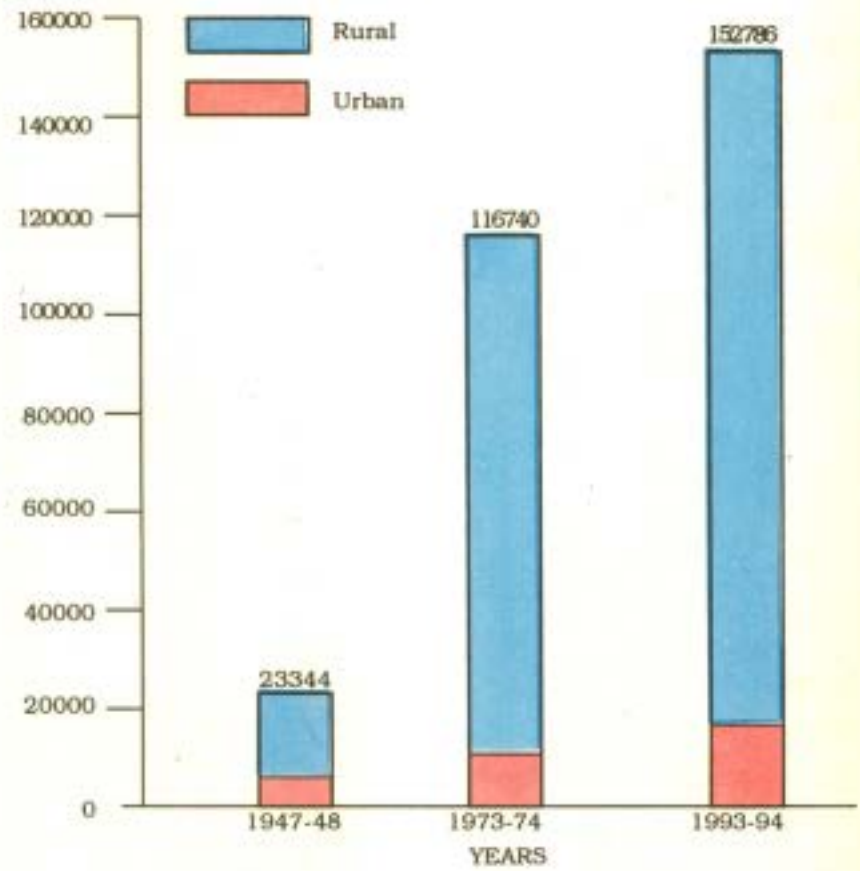

By the end of the 7th Plan, the National Postal Network encompassed 1,47,236 post offices of which 16,249 post offices were in the urban sector and 1,30,987 post offices in the rural areas. As on 31.3.94, there were 1,52,786 post offices in the country, out of which 16,804 are in the urban sector and 1,35,982 are in the rural area. On an average, a post office covers an area of 21.49 sq. kms. and a population of 5527 as per the 1991 Census.

The Planning Commission had originally approved a target for opening 500 departmental sub post offices (DSOs) and 3000 extra departmental branch post offices (EDBOs) during the 8th Five Year Plan (1992-97). However, while reviewing the Plan performance in the light of the continuous demand from Parliamentary Committee that the pace of extending postal facilities should be accelerated, the Department noted that there is a possibility of opening more post offices within the available resources. Accordingly, in consultation with the

Postal Traffic Since 1984-85
(Adjusted to Revenue)

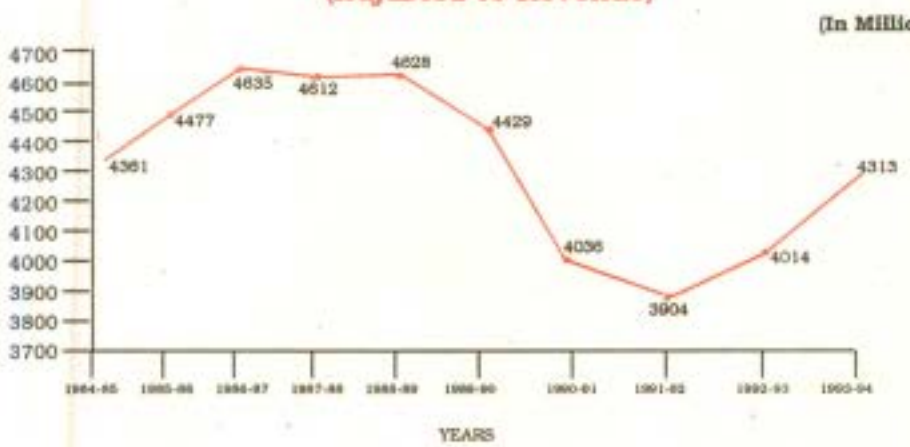

Articlewise Postal Traffic

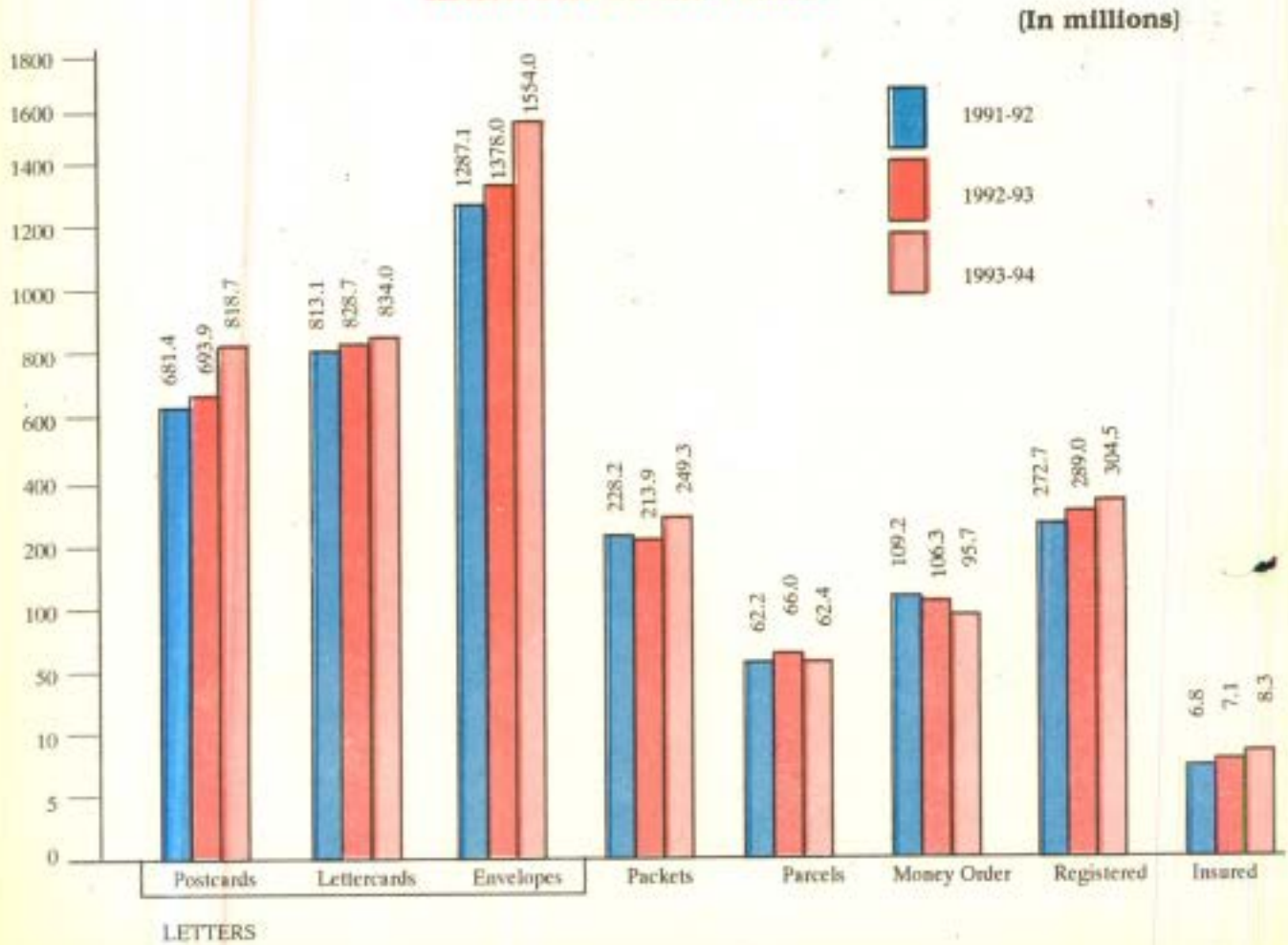

Planning Commission, the target for opening EDBOs was revised to 3600 and for DSOs to 650 within the resources already allocated. In the context of the 8th Plan, special emphasis is proposed to be given to hilly, desert and tribal areas for the expansion of the postal network. 1500 EDBOs are proposed to be opened under the Tribal Sub Plan during the period.

During the first two years of the 8th plan, 1302 EDBOs and 231 DSOs were sanctioned against a target of 1200 and 200 respectively. Due to financial constraints and ban on creation of posts, Ministry of Finance have suggested to scale down the proposed target of 800 EDBOs for 1994-95 to 80 EDBOs. Thus during 1994-95, it is proposed to open 80 EDBOs and 150 DSOs. Out of these, 23 EDBOs and 22 DSOs will be opened in tribal, hilly, desert and inaccessible areas.

Mail Volume

Domestic unregistered postal traffic handled during the year 1993-94 was 3549 million articles of mail consisting of 3078 million letters, 441 million packets and 30 million parcels. Domestic registered mail was 334 million articles. During this period, the Department of Post transmitted 98.7 million Money Orders aggregate value of which was Rs.31,826 million.

Speed Post

Speed Post has been one of the most popular as well as revenue earning service for the Department. This year a new Speed Post Centre was opened on 28.1.94 at Jodhpur taking the total tally of Speed Post Centres in the country to 63.

International speed post links were established on 14.10.93 with 13 more countries viz. Bermuda, Bhutan, Cape Verde, El Salvador, Iceland, Israel, Italy, Kenya, Kuwait, Latvia, Mauritius, Vietnam and Yemen Arab Republic raising the total number of countries connected to 74.

During 1993-94 the growth of speed post traffic was 47%. Total traffic generated during the year was approximately 1.09 crores articles. The revenue generated was to the tune of approximately Rs.50 crores registering growth of 57%.

Mail Operations

The Indian Postal system being by far the largest in the world in terms of geographical spread and population needs to be continuously monitored to ensure efficient functioning. This monitoring is being done in the field units at every level. In addition to induction of technology for providing better services and suitable monitoring, various categories of mail requiring special attention have been segmented and new channels for sorting and transmission of mail are being introduced. This segmented handling of mails will result in achieving two goals-to give adequate and exclusive attention to a particular segment of mail, to expedite their transmission and delivery, and secondly, the resultant benefit in attending to other mail expeditiously.

Speed Post Traffic
(In thousands)

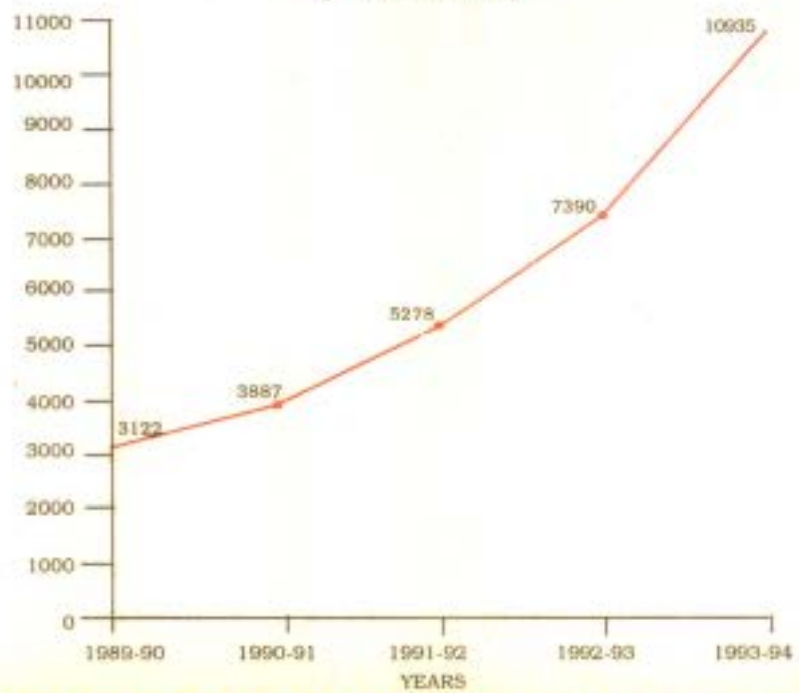

Metro Channel

In terms of quantity and time sensitivity, inter-metro mail constitute a sizeable bulk of mail traffic. It has, therefore, been decided to introduce a separate channel to handle mails between Delhi, Calcutta, Bombay, Madras, Bangalore and Hyderabad. In this case letters to these centres will be segregated at the initial handling stage. In many post offices light blue coloured letter boxes are being installed specifically for such letters. The letters will also be consigned in specially designed bags with special lables for purposes of easy identification. Specially earmarked mail motor vehicles and staff will be used to handle these mails and if necessary private airliners may also be used to transmit them on schedule. The aim is to deliver all such letters within 48 hours and bulk of such letters within 24 hours. This service is scheduled to commence in 1994-95.

Rajdhani Channel

The letters posted in State capitals meant for Delhi and vice-versa also constitute an important segment of mail. This channel aims at catering to such mail. Operation will be similar to that of Metro channel. This service is also likely to start in 1994-95.

Business Channel (Corporate Mail)

First class unregistered mail of Government, semi-Government and corporate bodies are referred to as business corporate mail which constitute another important segment of mail traffic. Traffic of such articles is heavy specially in important cities. As these mails are received in bulk, they have a serious impact on the overall arrangements for sorting and transmission of mails. The basic aim of the Business Channel is, therefore, to make special arrangements for such categories of mails and more so to remove the uncertainity of sudden dislocation of regular work thereby smoothening the process of sorting and transmission of other mails.

Business mail will be received in post offices or mail offices specialllly designated for the purpose at special counters. An important feature of this channel is to segregate the letters for bulk addressees at the sorting stage. Sorting, bagging and transmission will be done with special identification as provided for metro-channel. Implementation of this channel will be closely monitored by nominating an officer in each Circle as Project Co-ordinator. This service is also likely to start next year.

Panchayat Sanchar Yojana

The Department has a social obligation to provide basic postal communication facilities in areas where they are not currently available. Demands from public and various parliamentary fora require that the pace of providing these facilities should be accelerated. However, keeping in view on the one hand resource constraints in opening new post offices and the suggestion of Ministry of Finance and Planning Commission that the problem of revenue-expenditure gap of the postal system should be seriously addressed and on the other the need for providing basic postal facility in villages, particularly in gram panchayats an alternative scheme, namely, Panchayat Sanchar Yojana is being formulated. Under this scheme, the Panchayat, which enjoys a constitutional status and is also involved in developmental activity will be the nodal point for providing basic postal facilities on a contractual basis. The Panchayat will carry out the postal functions. The Panchayat will also select a functionary to discharge the function of Panchayat Sanchar Yojana and he will be paid commission/remuneration fixed by the Department.

Mail Motor Service

During 1993-94 departmental mail motor units functioned at 90 stations. To maintain as well as improve efficiency and ultimately achieve quicker transmission of mail, 124 new vehicles were purchased to replace the condemned old vehicles.

The total fleet strength of the mail motor vehicles at the end of 1993-94 stood at 1103. During the year, the fleet covered a total distance of 1.95 crores kilometers while the total expenditure incurred was Rs.18.94 crores. The average cost per kilometer was Rs.9.69.

Leasing of Post Office Premises

Recently a scheme has been introduced for leasing space in departmental post offices for operating STD/ISD, fax booths and for vending post office related items like packing materials, greeting cards etc. The purpose of the scheme is to facilitate the customer to attend to all post office related work under one roof. The scheme has already been introduced in a few post offices and has been welcomed by the customers.

Passport Application Form

1000 more post offices all over the country have been authorised to sell passport application forms on behalf of the Ministry of External Affairs. This is an addition to 1872 post offices which were already rendering this service.

Licensed Stamp Vendors

Under this scheme, the agent sells stamps and stationery at specified rates of commission from the post office.

Outstanding Balances in All Forms of Savings Including Certificates

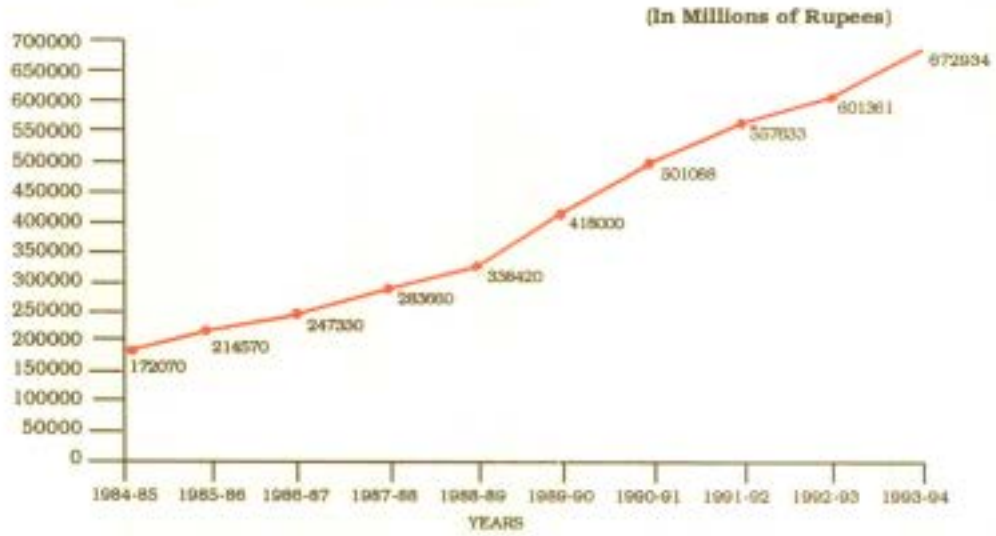

The commission has been increased from 1.5% to 5%. Now an agent can earn attractive remuneration through initiative and perseverance.

Philately

39 Commemorative/special postage stamps were issued from 1.4.93 to 31.3.94. These issues included two sets of four stamps each on 'Mountain Locomotives' and 'Flowering Trees' and one set of 2 stamps on Satyajit Ray.

Philatelic sale is managed all over the country through 50 philatelic bureaux and 199 counters. Seven State/ Circle level exhibitions were held from 1.4.93 to 31.3.94, details of which are given below:-

- Punpex-93 in Chandigarh Punjab Circle from 7.5.93 to 9.5.93.
- Uphilex-93 at Dehradun in UP Circle from 15.5.93 to 19.5.93.
- Mappex - 93 at Raipur in MP Circle from 28.6.93 to 30.6.93.
- Harpex-93 at Karnal in Haryana Circle from 17.9.93 to 19.9.93.
- Dakiana-93 in Delhi from 24.9.93 to 27.9.93.
- Tenapex-93 in Tiruchirapalli in Tamil Nadu Circle from 17.9.93 to 20.9.93.
- Appex-93 at Vijayawada, AP Circle from 16.9.93 to 19.9.93.

The National Philatelic Exhibition INPEX-93 was organised by the Department in Calcutta from 25.12.93 to 29.12.93, with the cooperation of the Philatelic Congress of India.

The Department also participated in the following international exhibitions by displaying exhibits of Indian stamps as also by sale of Indian stamps:-

- Indopex-93 at Surbaya, Indonesia held from 29.5.93 to 4.6.93.
- Bangkok-93 at Bangkok, Thailand held from 1.10.93 to 10.10.93.

Agency Services

Post Office Savings Bank

The Department of Post operates the following current schemes on behalf of the Ministry of Finance:-

- Saving Account Scheme
- Recurring Deposit Scheme
- Time Deposit Scheme -1 year, 2 years and 3 years scheme.
- Monthly Income Account Scheme
- Public Provident Fund.
- Indira Vikas Patras
- Kisan Vikas Patras
- National Savings Scheme, 1992.

Mahila Samriddhi Yojana

'Mahila Samriddhi Yojana'—a scheme which aims to promote self reliance and economic independence amongst rural women, was launched by the Prime Minister on 2nd October, 1993. The scheme encourages the habit of thrift amongst rural women so that they can use their savings for various household purposes and assure them security in times of need.

The Department of Woman and Child Development, Ministry of Human Resource Development is the nodal Ministry for this Central Sector

Total Number of Policies

(In Millions)

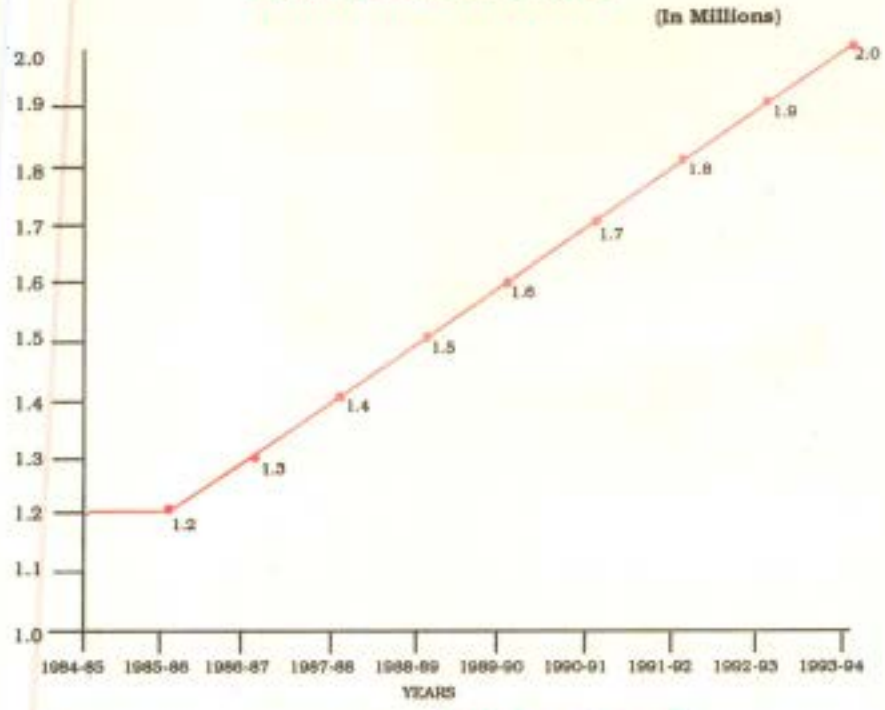

Total sum Assured

(In Millions of Rupees)

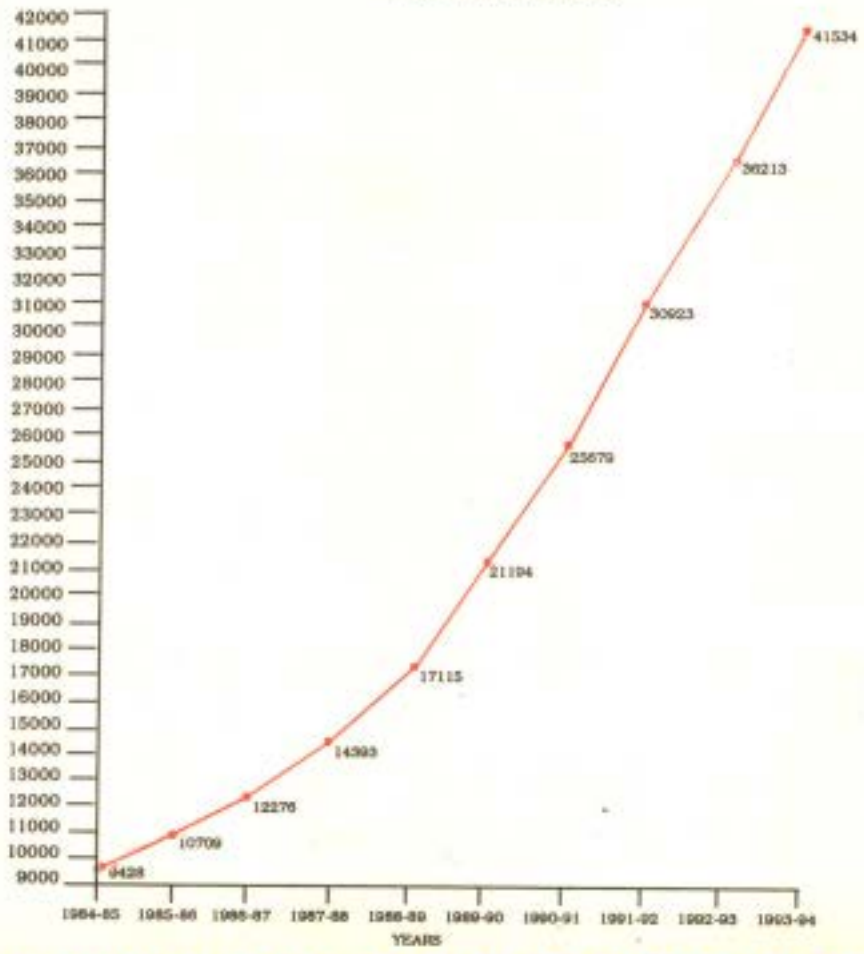

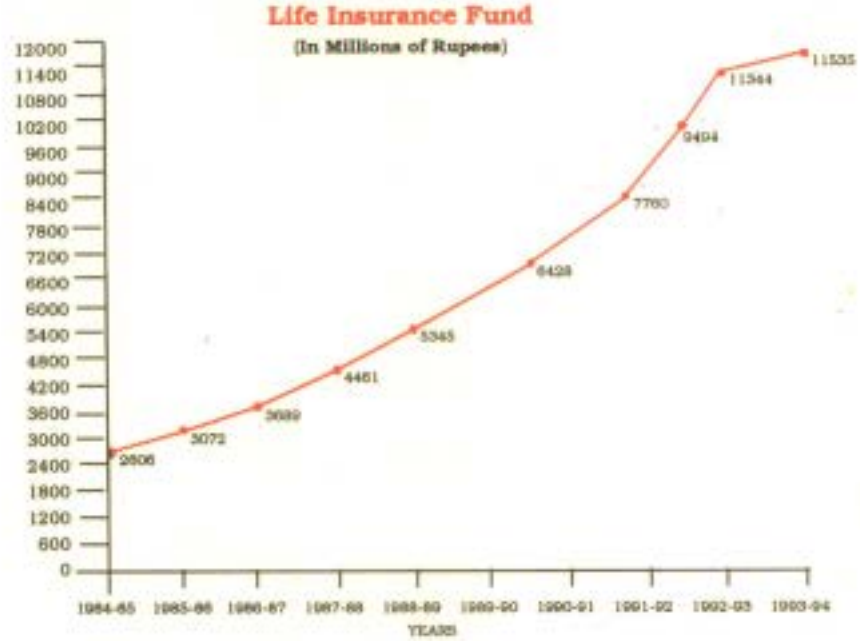

Scheme. The scheme is being implemented through a vast network of 1.32 lakh Post Offices in rural areas. Under the scheme every rural woman, aged 18 and above can open an MSY account in the nearest post office with an initial deposit of Rs.4/- or its multiples subject to a maximum deposit of Rs.300/-. The deposit, with a lock-in-period of 1 year, earns an incentive at the rate of 25% per annum subject to a maximum of Rs.75/-.

The scheme has received an enthusiastic response from rural women. Up to 31st March, 1994, 7,29,041 accounts with a total deposit of Rs.9,15,07,250/- have been opened all over the country.

Postal Life Insurance

Postal Life Insurance offers four types of policies viz., whole life, convertible whole life, endowment assurance and anticipated endowment assurance (20 year and 15 year term). The non-medical scheme is available upto a maximum sum assured of Rs.1 lakh, while the medical scheme is available upto a maximum sum assured of Rs.2 lakhs.

During the year 1993-94, 1.57 lakhs new policies were issued with a sum assured of Rs.595.39 crores and the total business at the end of the year stood at 19,91,723 policies with an aggregate sum assured of Rs.4153.36 crores at the end of 1993-94. The post office Insurance fund balance has risen from Rs.1134.4 crores in 1992-93 to Rs.1153.48 crores as on 31.3.1994. 60,644 claims for a total sum assured of Rs.60.62 crores were settled during 1993-94 as against 54,307 claims for a sum assured of Rs.47.26 crores during 1992-93 and loans of the value of Rs.11.42 crores were paid during the year as compared to Rs.8.95 crores during the previous year.

The expenses ratio in relation to premium income during 1993-94 works out to 10.48% as against 13.71% during the corresponding year 1992-93.

For the year 1994-95 the target for procurement of PLI business has been fixed at Rs.640 crores.

Postal Premises

In the year 1993-94 a sum of Rs.33.47 crores has been spent on construction of Postal, Administrative and other office buildings. The Department has incurred Rs.11.76 crores on construction of staff quarters, Rs.3.24 crores for purchase/aquisition of plots of land and Rs.34 lakhs on its Postal Training Centres and Staff College for land and building activities.

During the year, the Department has completed 111 Post office and other office buildings and 236 staff quarters. Construction of 104 post offices and other office buildings and 293 staff quarters have also been started.

Marketing and Commercial Publicity

India Post fully realises that in accordance with the Washington General Action Plan, side by side with updating and improving the quality of our service there is a necessity of an active marketing campaign. With this aim in view, print media as well as

electronic media are to be used to the fullest extent in promoting the Department and its activities. Our corporate image has been highlighted through advertisement in newspapers and periodicals on various occasions, including National Postal Day.

In the field of commercial publicity, the Department secured advertisements on postal stationery worth Rs.160.97 lakhs. Apart from English and Hindi, these advertisements to be printed on postal stationery are open for all regional languages.

Returned Letters

The Department's 15 Returned Letter Offices which process ultimately undelivered mail, handled 27.9 million pieces of mail during 1993-94, 55% of which were improved, re-addressed and delivered. 28% were returned to the senders after ascertaining their addresses.

Technology Induction

The basic function of the Department of Post is transmission of mail. However related services in the form of registered parcels and money order services are also being rendered in addition to limited banking and insurance activities as agency functions. With the advent of information technology, the Department of Post has made a modest attempt to introduce information technology into postal system so as to provide better services to the public, a better working environment to the employees and to provide new value added services based on technology.

For mechanising mail sorting in major metros, an attempt was made to introduce automatic integrated mail processing system at Bombay, which has started functioning from 1.4.93. Orders have since been placed for installation of a similar system at Madras.

Introduction of PC based multipurpose counter machines have gained wide acclaim from the public as it has resulted in great customer satisfaction. This equipment provides multiple transaction of accountable nature at a single window. Efforts are being made to bring more transcations within the purview of this computerised counter so that it brings in more customer satisfaction. Orders have been placed for providing 1000 more machines in various post offices in the country which will take total tally of such machines to 1852.

The Department is processing the introduction of satellite money order scheme. The first phase, which have been approved by the Government, provides for 75 micro earth stations to be installed in various states for transmission of money order advice. It is expected that the service will start operation in the year 1994-95. This will result in faster transmission of money order advice which will result in quick delivery of money order throughout the country. The department is also thinking in terms of using this network for more value added services.

In the field of savings bank operations, computerisation has been introduced in nine head post offices in Delhi, two head post offices in Bombay and the Chandigarh GPO. In Delhi in Parliament Street Post office CTD and RD schemes have been computerised and in Indraprastha Head Post Office MIS scheme has been computerised on experimental basis. Efforts are on for giving more customer satisfaction by providing more online services.

Till this year Postal LIfe Insurance operations had been computerised in 12 circles. During this year one more circle is being computerised and orders placed for computerisation of 6 more circles in 1994-95.

POSTAL FINANCE

The total revenue during the year 1993-94 was Rs.1105.17 crores, registering an increased receipt of Rs.31.27 crores i.e., about 2.91% against the preceeding year's receipts of Rs.1073.90 crores.

The net working expenses of the year was Rs.1312.26 crores against the previous year's expenditure of Rs.1165.71 crores (i.e. an increase of about 12.57%) and against the estimated expenditure of Rs.1290.00 crores projected in RE 1993-94. The increase was mainly due to payment of Interim Relief sanctioned with effect from 16.9.93 and increase in the ceiling limit of emoluments for Bonus etc. The revenue expenditure gap of the Postal Services during 1993-94 was Rs.207.09 crores as compared to Rs.91.81 crores during 1992-93.

REVENUE AND EXPENDITURE 1993-94

(As compared to 1992-93)

(In crores of rupees)

Particulars	1992-93	1993-94	Percentage change over previous year
Revenue			
Sale of Stamps	609.75	629.66	3.27
Postage realised in cash	268.63	288.28	7.31
Commission on Money Orders, Indian Postal Orders, etc.	135.68	145.05	6.91
Other receipts	59.84	42.18	29.51
Total	1073.90	1105.17	2.91
Expenditure			
General Administration	103.17	114.89	11.36
Operation	1132.23	1288.39	13.79
Agency Services	62.87	72.96	15.75
Others	350.91	390.55	11.30
Total Gross Expenditure	1649.18	1866.79	13.19
Less Recoveries	483.47	554.53	14.70
Net Expenditure	1165.71	1312.26	12.57

The Gross expenditure in important categories is given below:-

Particulars	1992-93	1993-94	Percentage change over previous year
Pay & Allowances			
Contingencies and Other items	1246.83	1442.03	15.93
Pensionary Charges	203.64	227.43	11.68
Audit & Accounts	37.65	42.49	3.32
Stamps & Postcard etc.	45.77	45.69	0.18
Stationery & Printing etc.	18.50	*22.53	43.68
Maintenance of Assets	9.14	*9.24	1.09
Depreciation	6.90	8.00	15.94
Petty Works	1.79	1.55	(-)13.40
Conveyance of Mails (Payment to Railways & Airmail Carriers)	78.96	67.78	(-)15.16
Total:	1649.18	1866.79	13.19

*Excluding Pay & Allowances.

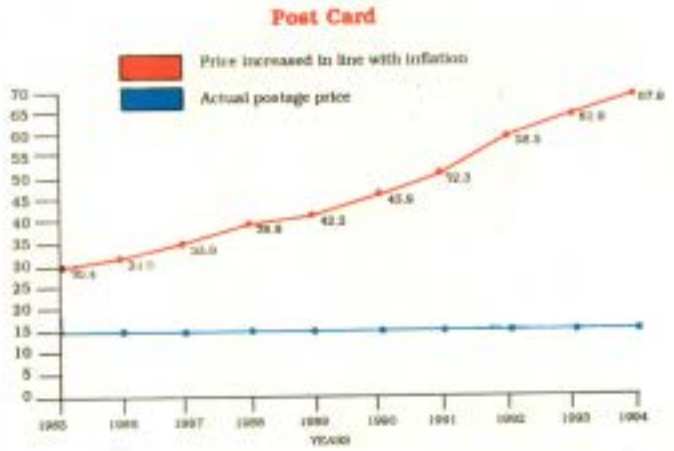

Letter Card

Revenue and Expenditure

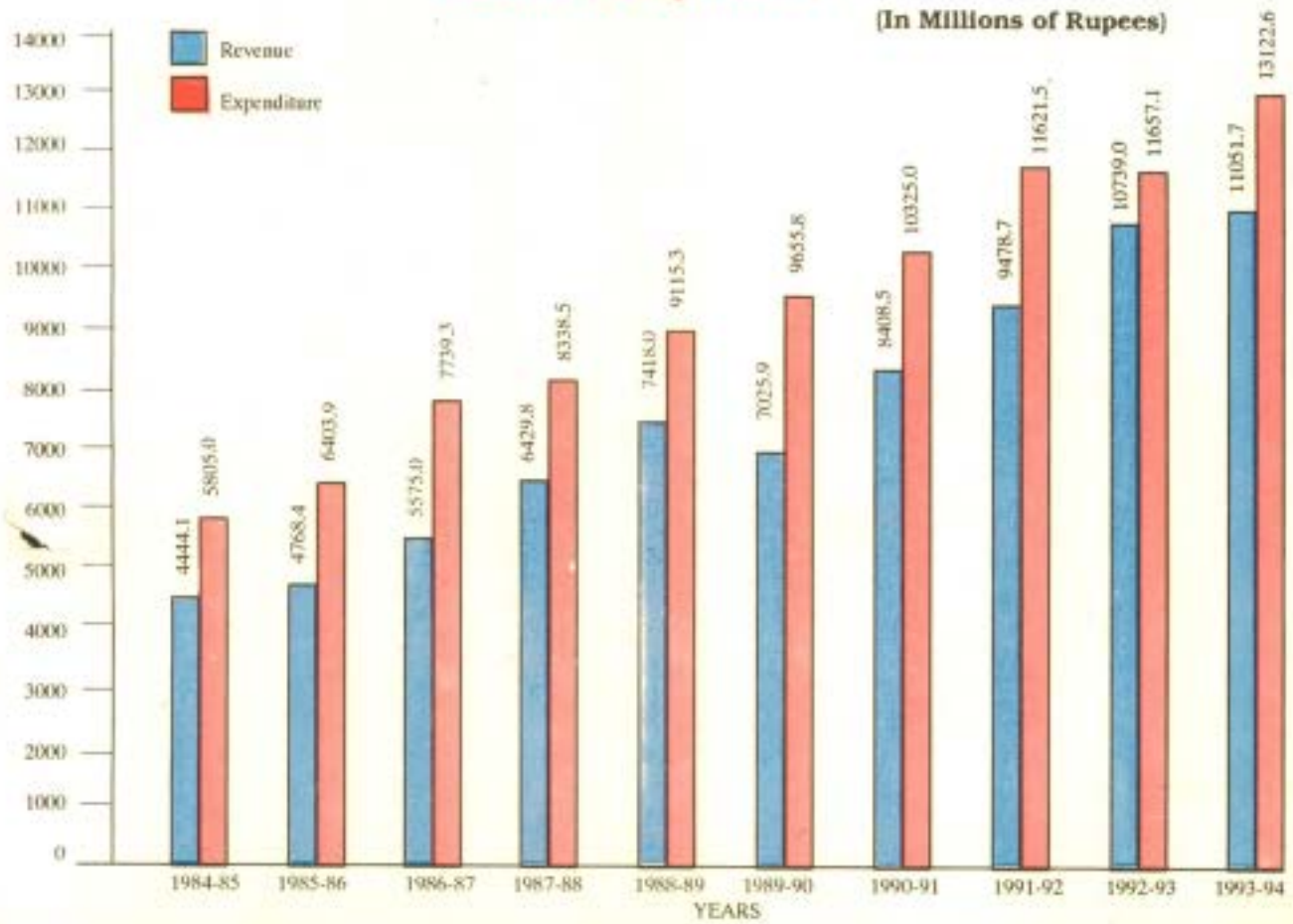

Cost of Service

The cost and revenue of main services for the year 1993-94 along with the position for the previous year are shown against each service below:-

(Figures in Rupees)

Service	1992-93		1993-94	
	Cost	Revenue	Cost	Revenue
Postcard	1.54	0.15	1.57	0.15
Printed Card	1.44	0.60	1.46	0.60
Letter Card	1.57	0.75	1.61	0.75
Letter	1.78	1.85	1.95	2.13
Parcel	22.11	17.02	19.40	16.46
Money Order	14.09	10.97	13.28	11.68
Registration	10.36	6.00	9.90	6.00
Insurance	13.76	11.01	13.36	14.78
Book Post				
Book Pattern and Sample Packet	2.28	1.79	2.20	2.07
Printed Books	2.94	1.52	2.78	1.56
Others	3.27	1.29	3.07	1.52

In the year 1993-94 the Departments recovery of working expenses on account of agency services was:-

(Rupees in crores)

1.	Savings Bank and Saving Certificates	:	513.50
2.	Military Pension	:	0.50
3.	Payment of Coal Mines and EPF/Family Pension and Misc. Services	:	6.30
4.	Payment of Railway Pension	:	2.73
5.	Postal Life Insurance	:	15.63
6.	Customs duty realisation	:	0.82
7.	Savings Bank Pairing Work	:	0.46
8.	Mahila Samriddhi Yojna	:	10.00
9.	Others	:	0.07
	Total	:	550.01

Capital Outlay

The expenditure on fixed assets in the year was Rs.59.25 crores. Of this 82.4% was on land and buildings and 17.6% on apparatus, plants and others. The value of the capital on fixed assets rose to Rs.572.48 crores at the end of the year. The net progressive Capital Expenditure to the end of the year financed from General Revenue was Rs.468.59 crores.

HUMAN RESOURCES

Manpower

Personnel continued to be the principal resource for the Indian Postal System. The total staff strength as on 31.3.94 was 5.98 lakhs, including 3.07 lakhs Extra Departmental Employees who man most of the services in the rural areas.

Training Programmes

The training infrastructure of the Department of Post consists of the following Training Institutes:

Postal Staff College of India, Ghaziabad.

Post and Telegraph Training Centre, Saharanpur.

Postal Training Centres, Vadodara, Mysore, Darbhanga and Madurai.

The Postal Staff College of India at Ghaziabad is an apex training institute catering to the training needs of the managerial cadres of the Department. The main objective of this college is to impart induction and in-service training to the officers of the Indian Postal Service with a view to inculcating in them:

- Requisite knowledge, skills and aptitude to enable them to make the Postal System effective and responsive to the needs of the people.
- Providing leadership to vocational training of operative cadres through the five Regional Training Centres.
- Undertaking research in spheres of management of the postal system, and
- Building up a Postal Data Bank and Document Centre.

In addition, workshops on different aspects of the postal services at the behest of international agencies such as the Universal Postal Union etc. are also organised for the benefit of officers belonging to Foreign Administrations. During the period from 1st April, 1993 to 31st March, 1994, 6 induction and 15 in-service courses were conducted by the Postal Staff College of India. In all 292 officers including 60 foreigners participated in these courses. The main objectives of the Regional Postal Training Centres are:-

- To impart induction training to Inspectors (Postal & RMS) and Time Scale Clerks.
- To impart in-service refresher training to Postal and Sorting Assistants, Supervisors, Inspectors, ASPOs, Postmasters etc; and
- To train officers promoted to middle managerial positions to equip them to shoulder higher responsibilities with confidence and develop appropriate managerial knowledge and skills required for independent management of Postal and RMS divisions.

Besides induction training, courses are also organised for officers belonging to Foreign Administrations if necessary at the Post & Telegraph Training Centre, Saharanpur. A total number of 14,347 officials have been imparted training during the period ending 31.3.94 in all the five Regional Training Centres. Special emphasis has also been given for imparting training in Hindi medium. Training duration and course contents are constantly reviewed. To cope with technology induction and to give adequate training to the personnel of the department, computers as well as other training aids like Video Rama Projection Systems for screening video films are being supplied to the centres.

Staff Relations

The Department endeavoured to maintain healthy and meaningful relations with the three federations and twenty-seven unions/associations of employees and EDAs. During the Year, three meetings of the Postal Departmental Council (JCM) were held in addition to 20 meetings of its committees, 8 periodical meetings and 8 meetings of the standing committees. Besides, 2 meetings of the Departmental Committee for EDAs were also held during the year. The main objective of the meetings was to find amicable solutions to the various demands of the employees and extra departmental agents.

Staff Welfare

The objectives of the Postal Services Staff Welfare Board are to promote, develop, organise and exercise overall control in respect of staff amenities and welfare, sports and cultural activities in the Department. The Board receives grants-in-aid for this purpose from the government. Voluntary contributions from staff and collection through sports and cultural activities are also arranged by the subordinate formations.

The funds of the Welfare Board are utilised for welfare activities like community centres, recreation clubs, relief in case of natural calamities, grant of scholarships, excursion trips, grants to help handicapped staff and

children, maintenance of vocational training centres, creches, schools and welfare schemes for SC/ST employees. Besides, funds are also earmarked for development of sports. During the year, special allocation of Rs.15.35 lakhs was made for assistance to flood victims and Rs.2 lakhs for earthquake victims.

Holiday Homes

The Department is running holiday homes at 19 locations for its employees and their families.

Sports

During the year 1993-94, the All India Postal Sports Board organised tournaments in Table Tennis (Madhya Pradesh), Weightlifting/Powerlifting and Best Physique (Haryana), Badminton (Orissa), Football (Bihar), Chess (Himachal Pradesh), Volleyball (Andhra Pradesh), Kabaddi (Maharashtra), Atheletics & Cycling (Kerala), Wrestling (Punjab), Basketball (West Bengal), Cricket (Rajasthan) and Hockey (Uttar Pradesh). All India Postal Cultural Meet was organised at Ahmedabad.

Efficiency Bureau

The Heads of Circles Meet, 1993 of all Chief Postmasters General was held on 29th and 30th July, 1993 followed by a Conference of Controllers Mail Planning Operations of all Metro Cities for cutting down delay in the transmission of mail. Important decisions aimed at improving the efficiency in the Department and for maximising customer satisfaction were taken. Study on Ledger Agreement in SBCO was carried out and a report thereof has been prepared.

Internal Work Study

The following work studies have been conducted/finalised:

- Deduction of tax at source from withdrawal of deposits made in NSS accounts in Post Offices.
- Work Study on the evolution of norms for the post of SDI, RMS is in progress.
- Review study relating to payment of Railway Pension through SB accounts report has been submitted and SIU has vetted the new norms.
- Work study for evolution of norms for sanctioning the Group 'C' staff connected with sale of IVP/Discharge of IVPs.
- Work study for evolution of norms for electronic adding and listing machines.
- Evolution of norms for Gr. 'C' staff connected with Speed Post Service.
- Evolution of norms for providing clerical assistance to SDI/ASPOs sub-divisions.
- Evolution of norms for work connected with the sanction of supervisory posts in MMS.
- Revision of norms for work connected with Ledger Agreement in SBCO.

Recognition of Higher Performance

Meritorious service is always recognised by the Department and employees whose merit needs recognition at the national level, have been honoured with Meghdooot Awards. For the year 1993-94, the following officials were recognised for their outstanding contribution to the Department and were awarded Meghdoot Award:

- Shri T.T. Thomas, EDBPM, Kerala Circle
- Shri K.J.Rathod, ED Messenger, Gujrat Circle
- Shri Rehmat Ali, Postman, Rajasthan Circle.
- Shri B.D. Vats, Guide, PA, Delhi Circle.
- Shri Jashobant Singh, Sorting Assistant, Orissa Circle.
- Shri Gulab Singh, SAS, Haryana Circle.
- Shri M.Umapathy, SRM, Tamilnadu Circle.
- Smt. Mallepally Nirmala, OA, Andhra Pradesh Circle.

Promoting Official Langauge

The Department, as per the policy of the Government of India, has been making sustained efforts to ensure the optimum use of Hindi as the Official Language. The Official Language Implementation Committee has already been constituted at the headquarter and also in all its circle offices and it reviews the progressive implementation of goals and directives in this regard from time to time. Necessary suggestions are issued towards rectifying the deficiencies which come to notice during the review.

With a view to review the implementation of the Official Language Act and the rules made there under, the Official Language Policy and compliance of the Annual Programme issued by the Government, inspection of the various offices of the Department are done from time to time. The deficiencies identified during the inspections are brought to the notice of the offices concerned alongwith suggestions. These measures have yielded desired results. The Parliamentary Committee on Official Language issues necessary instructions during the inspection of various offices of the Department to ensure the compliance of the suggestions made with regard to implementation of the Official Language Policy. Follow up action on these recommendations are also being

ensured. Funds are also provided to the circles for purchase of Hindi books for the circle offices as well as subordinate formations.

With a view to ensuring the maximum progressive use of Hindi as Rajbhasha, a scheme for organising 'Rajabhasha Sammelan' in every circle of the department, atleast once a year, has been introduced. Four Rajbhasha Sammelans have already been organised in the four circles located at Region 'C'. Effective steps are being taken to ensure solutions to the difficulties faced by them.

Instructions are also issued from time to time regarding the provision of training to officers and staff at the headquarters and the circles as well under various schemes initiated under the Hindi Teaching Scheme. By organising 'Hindi Workshops' in headquarters and the subordinate offices of the Department, the staff and officers are being trained to work in Hindi.

With a view to gear up the implementation of Hindi through the incentive and goodwill policy of the government, different schemes have been introduced for honouring the officials with cash prizes.

Secretary (Post) is also taking a personal interest in this regard to ensure constant monitoring so that the implementation of the Official Language Policy can be done in a more effective-manner.

PART-2
ANNUAL REPORT
1994-95

In 1994-95, the Department of Post initiated a number of strategic steps to induct appropriate, cost effective technology into the postal system at the earliest and with a time bound approach, to ensure that the services are of an assured quality and responsive to customer needs. Measures were also taken to introduce new services based on technology to meet the demand for quicker and more reliable and responsive services. The basic objective underlying all the activities undertaken in the current year has been to convert the postal system into a truely modern, world class organisation capable of meeting the present and future needs of its customers.

Mail Operations

The handling of mail has been segmented to meet specific requirements of customers. The **Metro channel**, which provide time-bound processing of pincoded mail amongst metros, has been introduced with effect from 2.4.94. **Rajdhani Channel** which similarly provides speedy processing of pincoded mail between state capitals and New Delhi has been introduced with effect from 16.5.94. The **Business Channel** which ensures processing of business mails within a time schedule has been introduced with effect from 1.7.94.

An **Express Parcel Service (EPS)** to provide a reliable and time-bound service has been introduced with effect from 1.12.94 both ways between Delhi-Bombay, Delhi-Calcutta and Delhi-Madras. 56 APO and 99 APO have been included in the national network of speed post with effect from 15.11.94.

Corporate Planning

The main objective of the 8th Five Year Plan of the Department of Post is to modernise the postal system through induction of new technologies and to provide quicker and more efficient service to customers, besides introduction of new services specifically tailored for the customers. In order to achieve these objectives, the emphasis during the current year has been on implementing the programmes for modernisation and upgradation of technology in a more focussed manner so as to ensure more efficient and responsive customer service, enhance employee satisfaction through friendly, clean and modern work environment and also provide new value-added service to meet customer needs.

A time bound programme for modernising counter services and other front office activities during the current year in 53 selected important post offices has been initiated. Such modernisation is centred around the computer based counter machines, already supplied, and involves upgrading the counter functions with introduction of modern technology, to provide efficient, responsive and hassle free service to the customer and also enhance employee satisfaction through improved ergonomies. 53 selected important offices are being fully modernised under this programme during the year 1994-95.

The modernised retail outlets using state of the art technology will provide efficient and relevant services at the urban centres where the post has an important role to play to support and sustain business and commercial activities. Similarly the new strategy of segmented mail processing and delivery will ensure time-bound handling of the more time - sensitive mails. These measures will also help to decongest the system itself and consequently improve the flow of other mails. In order to further improve the operational efficiency in the peripheral units, the Department has a programme of providing modern operational equipments which will help eliminate drudgery from the postal operations. 100 operative offices are targetted for coverage under this programme during 1994-95.

A programme to achieve substantial improvement in the work environment and corresponding increase in customer satisfaction, primarily through more effective and focussed management, has also been introduced in the current year. Under this programme, 10 operative offices in each Postal Division in the country have been identified for improving the quality of service through better management.

One of the approved plan schemes of the Department is to provide letter box facility to every village having a population over 500, which has not

yet been provided this facility. The Department's objective in this regard is to achieve this target fully during the 8th plan period. As on 31.3.94, it was estimated that there were 71,075 villages with population over 500 which had not yet been provided with letter box. Of these 51,327 villages are proposed to be provided this facility by 31.3.95.

Satellite Money Order

In order to speed up transmission of money order and thus make this section more useful, the first phase for the Satellite Money Order Service envisaged installation of micro-earth stations at 75 locations in the country, each station having a VSAT (Very Small Aperture Terminal) and other computer peripherals. A pilot project was initially launched at 6 locations Delhi, Madras, Bangalore, Lucknow, Patna, and Shimla in 1994-95. This system has since been dedicated to the nation by the Hon'ble Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao on 16.12.94. During the current year 20 more stations are proposed to be set up. This net work will speed up transmission of money order advice and ultimately result in much speedier delivery of money orders. Making of the modern technology provide the network for speedy data transmission through the VSAT network the department is also introducing new value added services through which specifically meet customer needs for quick and reliable transmission of text and data.

Hybrid Mail Service

Hybrid mail is a new service for transmission of material through the satellite channel using the VSAT network and delivery to the addressee either through the postman or in a printed format or through a floppy. Through the Hybrid Mail Service any material irrespective of length can be transmitted instantly through the satellite network by use of computers. Customers will have the option of bringing the material on a floppy or otherwise they will be provided with computer facility at the post office where such booking is made. At the receiving station they can have the option of downloading the data in their own computer in case they are connected through a modem and a telephone. Otherwise, the printed message can either be collected by them or be delivered at their premises. The service was inaugurated by Shri Sukh Ram, Hon'ble Minister of State for Communications on 14.1.95. Other value added services, specially to meet the requirements of the corporate sector for quick cash transfer and such other facilities are being worked out for introduction shortly. In line with the Department's heightened awareness for customer satisfaction, important post offices located in busy city centres, are being provided with Postshoppe run by private owners where customer get various items often required for packages, parcels and preparing letter and other useful items of utility and also ISD/STD facilities for customers.

Counter Mechanisation

This scheme seeks to provide the facility for multiple postal services including Savings Bank at a single window in the post office reducing waiting time. While orders have been placed for procurement of more PC based multi-purpose counter machines bringing the total number of such machines to 1852, till November 1994, 1060 mechines have already been installed. The rest of the machines are in the process of being installed. Optimising the benefits of the machines, selected important post offices are being fully modernised to provide more efficient and responsive counter services.

Induction of Mechanical Equipment

For better stamp impression on postal articles, efforts are on for supplying more stamp cancelling machines as well as good quality hand stamp to the post offices. Out of 270 stamp cancelling machines ordered for procurement, 180 machines have already been supplied and the rest is likely to be supplied by March, 1995. Out of 25,000 hand stamps ordered to be manufactured by Indian Ordnance Factory, Calcutta, 11,000 have since been supplied.

Expansion of Postal Network

As against a target of opening 80 EDBOs and 150 DSOs during this Annual Plan, 56 proposals for opening post offices are under process upto 31.12.94.

The Department has also formulated a new scheme called the `Panchayat Sanchar Yojana' to provide basic postal facilities in villages on a contractual basis using the panchayat network. This scheme is scheduled to be inaugurated during the current year.

Philately

Twenty-four commemorative/ special stamps have been issued from 1.4.94 to 31.12.94. These issues include stamps on the maestro of movie cinema Satyajit Ray, the 125th anniversary of Mahatama Gandhi and the centenary celebration of the Baroda Museum. The department participated in two International stamp exhibitions—Singapex-94 in Singapore from

31.8.94 to 4.9.94 and Phila-korea-1994 in Seoul from 16.8.94 to 25.8.94. The following four state level philatelic exhibitions were held upto 31.12.1994- Bipex-1994 in Patna, Karnapex—1994 in Bangalore, Gujpex-1994 in Ahmedabad and Mahapex-1994 in Bombay.

Universal Postal Union

The 21st Congress of the Universal Postal Union was held at Seoul, Republic of Korea from 22nd August to 14th September, 1994. A high level Indian delegation led by Shri Sukh Ram, Minister of State for Communications, represented India at the Congress. At the Congress, India was elected to the Council of Administration and to the Postal Operations Council. Further, India was nominated as a Chairman of the Finance Committee of the Council of Administration for a period of five years. India is also a member of the Strategic Planning Working Party of the Council of Administration.

The Annual Session of the Asian Pacific Postal Union Executive Council and that of the Governing Board of the Asian Pacific Postal Training Centre was held at Surfers Paradise, Australia in June-July, 1994. A two member Indian delegation led by Secretary (Post) represented India.

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

The Department of Post hosted the second meeting of the SAARC Technical Committee on Communications in New Delhi on 4th and 5th May, 1994. Participants from all SAARC countries attended the meeting which discussed various issues for promotion and cooperation in the field of Post & Telecommunication in the region. Secretary (Post) attended the meeting of the SAARC Standing Committee held at Dhaka in July 1994 and presented the Report as Chairman of the SAARC Technical Committee on Communications.

Bilateral Cooperation

A high level delegation from Israel led by the Minister for Communications, Science & Arts visited India from 27.11.94 to 1.12.94. During his visit, a bilateral Agreement for cooperation in the field of Telecommunications and Postal Services was signed.

A delegation led by the Managing Director, Australia Post Corporation visited India in October, 1994 for sharing Australia's expertise in Electronic Point of Sale (EPOS) for modernizing counter operation in Postal Services.

Use of Renewable Sources of Energy

The Department is making efforts to use renewable sources of energy as a measure to protect the environment. A pilot project covering ten identified regions in the country has been formulated for use of solar energy through photovoltaic equipment for lighting rural post offices. The programme is being implemented in collaboration with the Ministry of Non-Conventional Energy Sources.

Heads of Circles Conference

The Heads of Circles Conference of all CPMsG and Regional Postmasters General and other Sr. Administrative Grade officers was held at New Delhi for two days on 15th and 16th of July, 1994. The main thrust of the discussions was to examine the ways and means of bringing in excellence in mail services and in the introduction of technology.

Mahila Samriddhi Yojana

This new scheme which provides for economic development and independence of rural women has been very popular and till 21.12.94, 72,04,193 accounts have been opened and the amount deposited is Rs.65,90,20,356.

Postal Life Insurance

The postal life insurance scheme, which first came into existence only for defence personnel and later extended to Government and Semi-Government employees, is now to be extended to the rural public also. The scheme has been firmed up and is likely to be introduced shortly.

Official Language

With a view to give a filip to the use of Official Language in day-to-day official work, the Secretary, Department of Post held two meetings with the senior officers of the Department on 13th July, 94 and 16th August, 94 and reviewed the position of the implementation of the Official Language Policy of the Union in the Department.

Hindi Fortnight was observed from 14th to 28th September, 94 in the department and its subordinate formations. During the fortnight various programmes were organised with a view to accelerate the use of Hindi as Official Language. On Hindi-day i.e. 14th September, 94, Secretary (Post) addressed the officers highlighting the need for the successful implementation of the Official Language Policy of the Union.

A special meeting/workshop of the Supervisory Officers was held on 29.11.94 for their contribution towards furtherance of the cherished objectives enshrined in the Constitution for development of the Official Language.

Registration of Operators of Cable T.V. Network

From Sept. 94 the Head Post Masters incharge of Head Post Offices have been authorised as Registering Authority of Cable T.V. Operators in their accounts jurisdiction. As many as 4485 registrations have been made by the end of January, 95 all over the country.

The Postal Services Board

This year has also witnessed a number of changes in the Postal Services Board. Now, the Board comprise Shri S.C. Mahalik as Chairman, and S/Shri P.K. Bagchi, A.V. Rao and C.J. Mathew as Members. Shri K. Diesh, Sr. Deputy Director General (Quality Management), is also the Secretary of the Postal Services Board.

Details of Audit Paras included in the C&AG Report and Outstanding as on 20.1.95

	Audit Report Number and Year	Paragraph No.	Subject
1.	No. 7 of 1994	1.9	Agency functions.
2.	No. 7 of 1994	1.10	Finance Accounts.
3.	No. 7 of 1994	1.11	Advances from Public Account.
4.	No. 7 of 1994	3.1	Postal Staff College and Postal Training Centres.
5.	No. 7 of 1994	3.2	Internal Check Organisation.
6.	No. 7 of 1994	4.1	Non-Implementation of Plan for Dedusting Plants.
7.	No. 7 of 1994	4.2	Vacant Staff Quarters at Nagpur.
8.	No. 7 of 1994	4.3	Delay in procurement of a Machine for converting left over paper.

Action taken note relating to the Paras 1.10, 1.11, 3.1, 3.2, 4.2 have been sent to Audit for vetting.

STATISTICAL SUPPLEMENTS

Table-1

(Rupees in crores)

Financial Working	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (B.E.)
1. RECEIPTS	702.59	840.85	947.87	1073.90	1105.17	1170.00
EXPENDITURE						
2. General Administration	80.25	83.28	90.79	103.17	114.89	117.19
3. Operation	864.29	905.49	1042.76	1132.23	1288.39	1353.27
4. Agency Services	44.07	46.31	54.84	62.87	72.96	75.64
5. Audit & Accounts	28.99	30.88	33.30	37.65	42.49	47.00
6. Engineering Maintenance	16.24	11.48	18.54	21.51	24.82	29.20
7. Amenities to Staff	11.51	10.67	11.77	12.90	13.39	17.00
8. Pensionary charges	110.18	150.31	182.28	203.64	227.43	240.00
9. Stamps, Stationery & Printing	62.07	63.16	66.19	66.23	72.27	83.28
10. Depreciation	5.19	5.40	6.00	6.90	8.00	9.00
11. International Cooperation	0.76	1.09	0.08	1.81	1.97	2.56
12. Social Security & Welfare Programmes	0.25	0.19	0.20	0.27	0.18	0.30
13. Gross Working Expenses (Total of Items 2 to 12)	1223.80	1308.26	1506.75	1649.18	1866.79	1975.14
14. Less-Credits to Working Expenses	258.22	275.76	344.60	483.47	554.53	659.00
15. Net Working Expenses (Item 13 minus 14)	965.58	1032.50	1162.15	1165.71	1312.26	1316.14
16. Net Receipts (Item 1 minus 15)	(-)262.99	(-)191.65	(-)214.28	(-)91.81	(-)207.09	(-)146.14
17. Dividend to General Revenues	-	-	-	-	-	-
18. Surplus (+)/Deficit(-) (Item 16 plus 17)	(-)262.99	(-)191.65	(-)214.28	(-)91.81	(-)207.09	(-)146.14

Table - 2

Capital Outlay During and Upto the end of 1993-94.

(Rupees in crores)

S.No.	Particular of Assets	During 1993-94	Upto the end of 1993-94
A.	**FIXED ASSETS**		
1.	Land	3.25	52.46
2.	Building	45.56	456.19
3.	Railway Mail Vans owned by Post Offices	-	8.61
4.	Apparatus and Plant	7.25	37.46
5.	Motor Vehicles	3.19	17.22
6.	Other Expenditure	-	0.54
7.	Gross Fixed Assets	59.25	572.48
8.	Deduct-Receipts and Recoveries	0.01	0.74
9.	Deduct-Expenditure met from Posts & Telegraphs Capital Revenue Fund	-	1.29
10.	Deduct-Amount of contribution from Revenue	-	27.86
11.	Deduct-Depreciation on historical cost transferred from Revenue	8.00	66.92
12.	Total Deductions (i.e. items 8 to 11)	8.01	96.81
13.	Net fixed Assets (i.e. items 7 minus 12)	51.24	475.67
B.	**OTHER ASSETS**		
14.	Consumer Co-operative Societies Share Capital contribution	-	-
15.	Civil Engineering Suspense	(-) 2.17	(-) 7.08
16.	Total Other Assets (Item 14 plus 15)	(-) 2.17	(-) 7.08
17.	Total Capital Outlay financed from General Revenues (Items 13 plus 16)	49.07	468.59
18.	Deduct-portion of Capital Outlay financed from ordinary Revenues	-	1.05
19.	Total Capital Outlay (voted) (i.e. item 17 minus 18)	49.07	467.54

Table - 3

Number of Post Offices as on 31st March, 1994.

S.No.	State/Union Territories	Urban	Rural	Total	Area served by a Post Office (Sq. Kms)
STATES					
1.	Andhra Pradesh	1383	14820	16203	16.97
2.	Assam	300	3507	3807	20.60
3.	Arunachal Pradesh	13	270	283	295.91
4.	Bihar	723	11047	11770	14.70
5.	Goa	57	192	249	14.86
6.	Gujarat	812	8085	8897	22.01
7.	Haryana	313	2269	2582	17.12
8.	Himachal Pradesh	114	2612	2726	20.42
9.	Jammu & Kashmir	195	1388	1583	140.23
10.	Karnataka	1336	8445	9781	19.16
11.	Kerala	695	4339	5034	7.72
12.	Maharashtra	1464	10815	12279	25.08
13.	Madhya Pradesh	1134	10080	11214	39.54
14.	Manipur	35	636	671	33.27
15.	Meghalaya	31	447	478	46.98
16.	Mizoram	33	350	383	55.04
17.	Nagaland	19	280	299	55.44
18.	Orissa	596	7476	8072	19.28
19.	Punjab	476	3361	3837	13.12
20.	Rajasthan	929	9353	10282	33.34
21.	Sikkim	13	183	196	36.20
22.	Tamil Nadu	2352	9743	12095	10.67
23.	Tripura	50	651	701	14.95
24.	Uttar Pradesh	2080	17955	20035	14.69
25.	West Bengal	1099	7371	8470	10.47
UNION TERRITORIES					
1.	Andaman & Nicobar	12	85	97	85.04
2.	Chandigarh	43	7	50	2.28
3.	Delhi	455	96	551	2.69
4.	Dadar & Nagar Haveli	1	33	34	14.44
5.	Daman & Diu	4	13	17	6.59
6.	Lakshadweep	-	10	10	3.20
7.	Pondicherry	37	63	100	4.92
	All India Total	16804	135982	152786	21.49

Table - 4

SAVING BANK - Outstanding Balances

(Number in Lakhs)
(Amount in crores of Rupees)

	1989-90		1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount	No. of Account	Amount
Saving Bank	476	3766	647	3976	466	4376	375	4590	426	4881
CTD	67	383	83	270	77	202	77	108	76	2
Recuring Deposits	334	2255	385	2638	414	3094	439	3631	501	4308
Time & Fixed Deposits	10	3830	12	2973	13	2861	13	2717	13	2979
National Saving Scheme	34	2516	30	4592	25	6755	26	7061	23	6893
Monthly Income Scheme	13	1535	13	2340	11	2720	14	3348	20	4832
Total	934	14285	1170	16789	1007	20008	944	21455	1059	23895
Savings Certificates		27515		33320		35756		38681		43398
Grand Total		41800		50109		55764		60136		67293

Table - 5

Postal Life Insurance

Year	New Business		Total Business in force		Life Insurance Fund
	No. of Policy (in lakhs)	Sum Assured (Rs. in crores)	No. of Policy (in lakhs)	Sum Assured (Rs. in crores)	(Rs. in crores)
1984-85	1.12	153.0	11.56	942.8	260.6
1985-86	1.01	160.4	12.16	1070.9	307.2
1986-87	1.03	179.3	12.81	1227.6	368.9
1987-88	1.20	232.9	13.62	1439.3	446.1
1988-89	1.37	294.9	14.58	1711.5	534.5
1989-90	1.63	432.5	15.79	2119.4	642.8
1990-91	1.56	476.3	16.92	2567.9	776.0
1991-92	1.60	558.5	18.04	3092.3	949.4
1992-93	1.51	576.8	19.00	3621.3	1134.4
1993-94	1.57	595.4	19.92	4153.4	1153.5

Table - 6

PERSONNEL : Actual Strength (including those on deputation and training outside the department) as on 31.3.94.

A. GAZETTED

Secretary (Posts)	1
Member, Postal Services Board	2
Sr. DDG, Secretary, Postal Services Board	1
Indian Postal Service	
Chief Postmaster General	6
Senior Administrative Grade	67
Junior Administrative Grade	123
Time Scale	139
Postmaster Service	979
P&T Accounts & Finance Service	
Senior Administrative Grade	1
Junior Administrative Grade	10
Time Scale	16
Accounts Officers & Asstt. Accounts Officers	676
Central Secretariat Service	67
Civil Wing	
Chief Engineer	1
Others	236
Other General Central Services	199
Total	2524

Non Gazetted	Group 'C'	Group 'D'	Total
Directorate	494	163	657
Post Offices	198070	33584	231654
Railway Mail Service	26422	19217	45639
Mail Motor Service	2177	652	2829
Others	3796	3098	6894
Total	230959	56714	287673
Total Departmental			290197
B. EXTRA DEPARTMENTAL			307466
Grand Total (A+B)			597663

Table - 7

Number of Employees - Scheduled Castes/Tribes as on 31-3-1994

	Scheduled Castes	Percentage to Total no. of Employees	Scheduled Tribes	Percentage to Total no. of Employees
Group 'A'	89	14.63	27	4.44
Group 'B'	211	11.01	45	2.34
Group 'C'	41075	17.78	13584	5.88
Group 'D' (Excluding Sweepers)	10359	18.64	3433	6.17
Group 'D' (Sweepers)	736	63.61	50	4.32

Table - 8

Number of Employees - Ex-Servicemen as on 31-3-1994

	Ex-Servicemen	Disabled Ex-Servicemen
Group 'A'	-	-
Group 'B'	-	-
Group 'C'	2281	140
Group 'D'	519	27

Parliament Street Head Post Office, New Delhi.

Museum Road Sub-Post Office, Bangalore.

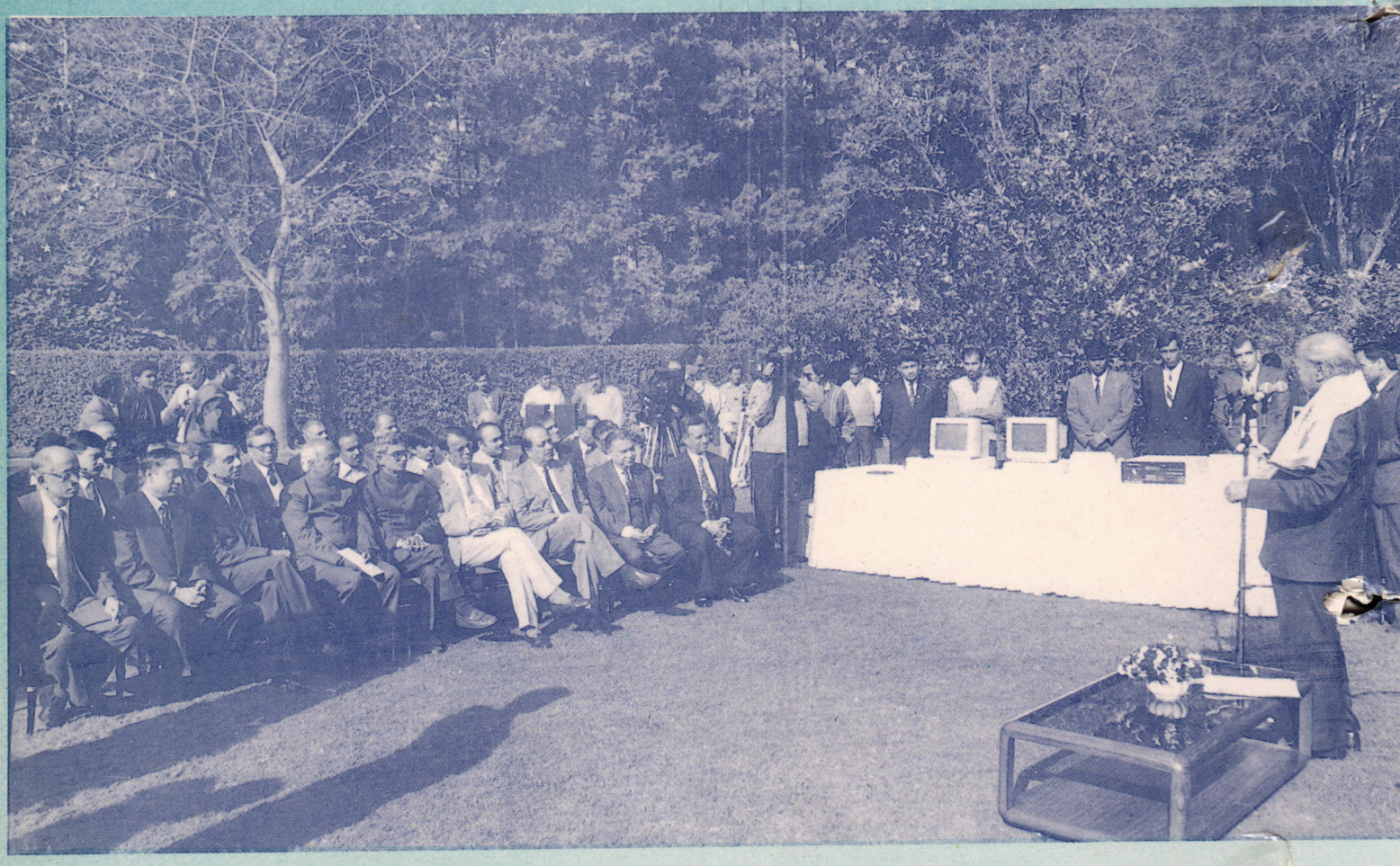

Dedication of Satellite Money Order Service by
Hon'ble Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao.